सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

# परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 309, नई दिल्ली । शुक्रवार, 17 जनवरी 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

03 आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है.....
06 भारत में 76वें गणतंत्र दिवस (2025) के अवसर पर शिक्षा की स्थिति
08 300 यूनिट मुफ्त बिजली के बदले उपभोक्ताओं को मिल रहे हैं 'स्मार्ट मीटर'

# दिल्ली-एनसीआर से फिर हटा ग्रैप-4

## प्रदूषण में कमी आने से लिया गया निर्णय

ठंड के प्रकोप के साथ लोग प्रदूषण की भी मार झेलने को मजबूर हैं। बृहस्पतिवार को दिल्ली में हवा की गति कम होने से वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बरकरार रही। ऐसे में लोगों ने बेहद खराब हवा में सांस ली।

संजय बाटला

**नई दिल्ली।** दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में कमी आने से गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चरण-4 के तहत प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। कल शाम को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 396 था। इसी को देखते हुए वायु गुणवत्ता पर केंद्र के पैनल ने ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू की थीं। अब ग्रैप-3 के तहत पाबंदियां लागू रहेंगी। जिसमें धूल पैदा करने वाली व वायु प्रदूषण फैलाने वाली सीएंडडी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम पर पाबंदी रहेगी।

### ग्रैप तीन के तहत इन कार्य पर रहेगी पाबंदी

-पूरे एनसीआर में धूल पैदा करने वाली व वायु प्रदूषण फैलाने वाली सीएंडडी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।

-बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम।

-पाइलिंग कार्य, सभी विध्वंस कार्य।

-ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना।

-ईंट/चिनाई कार्य।

-प्रमुख वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य, हालांकि, एमईपी (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग) कार्यों के लिए छोटी वेल्डिंग गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।

-सड़क निर्माण गतिविधियां और प्रमुख मरम्मत।

-परियोजना स्थलों के भीतर व बाहर कहीं भी सीमेंट, फ्लाई-ऐश, ईंट, रेत, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग/अनलोडिंग।

-कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही।

-विध्वंस अपशिष्ट का कोई भी परिवहन।

### ग्रैप-4 में थीं ये पाबंदियां

- दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी। हालांकि, जरूरी सामान लाने वाले व सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों पर पाबंदी से छूट दी गई थी।

- दिल्ली में पंजीकृत मध्यम व भारी डीजल संचालित माल वाहनों पर प्रतिबंध। जरूरी सामान वाले वाहनों को थी छूट।

- एनसीटी दिल्ली व एनसीआर में डीजल चलित चार पहिया वाहनों पर थी रोक। हालांकि, आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई थी। इस श्रेणी में केवल बीएस-6 वाहन चल सकते थे।

- एनसीआर में उद्योगों पर पाबंदी थी। जहां पीएनजी ईंधन की सुविधा नहीं थी और सरकार द्वारा अधिकृत सूची से बाहर के ईंधन के उपयोग पर थी रोक। हालांकि, दूध व डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट दी गई थी।

- निर्माण व विध्वंस गतिविधियों पर रोक। इसके अलावा फ्लाईओवर, राजमार्ग, पुल व पाइपलाइन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक।

- एनसीआर राज्य सरकारें सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट देने का था प्रावधान।

- राज्य सरकारें स्कूल व कॉलेज को बंद करने के साथ गैर आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर सकती थी।

- डीजल जनरेटर सेट पर प्रतिबंध

### हवा की गति कम होने से वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बरकरार

ठंड के प्रकोप के साथ लोग प्रदूषण की भी मार झेलने को मजबूर हैं। बृहस्पतिवार को हवा की गति कम होने से वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बरकरार रही। ऐसे में लोगों ने बेहद खराब हवा में सांस ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 302 दर्ज किया गया, जोकि बेहद खराब श्रेणी में है। साथ ही, अधिकतर इलाकों में हवा बेहद खराब रही। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषकों के फैलाव के लिए मौसम संबंधी स्थितियां बेहद प्रतिकूल होने से स्थिति बिगड़ रही है।

### एनसीआर में प्रदूषित शहर का एक्यूआई

दिल्ली - 302
गाजियाबाद - 195
नोएडा - 180
गुरुग्राम - 161
ग्रेटर नोएडा - 133
फरीदाबाद - 127

*(नोटः आंकड़े सीपीसीबी के मुताबिक)*

# 17-21 जनवरी तक दिल्ली में कई सड़कों पर डायवर्जन

## जानें से पहले देख लें रूट प्लान वरना होगी भारी मुसीबत

संजय बाटला

गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के चलते दिल्ली में 17 से 21 जनवरी तक कई रास्तों पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को ट्रैफिक प्रतिबंधों की जानकारी दी है। जानिए किन रास्तों पर जाने से बचना है और किन वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस की परेड से पहले कर्तव्य पथ पर शुक्रवार से रिहर्सल शुरू होगी।

**नई दिल्ली।** राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड से पहले कर्तव्य पथ पर शुक्रवार से रिहर्सल शुरू होगी। ऐसे में कई रास्तों पर यातायात प्रभावित रह सकता है। इसी को लेकर यातायात पुलिस ने लोगों की सुविधा के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में बताया गया है कि 17 से लेकर 21 जनवरी तक लोगों को किन रास्तों पर जाने से बचना है और किन्हें नजरअंदाज करना है।

दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी में कहा कि कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड रिहर्सल की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए विशेष ट्रैफिक व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था 17, 18, 20 और 21 जनवरी के लिए की गई है। एडवाइजरी के अनुसार कर्तव्यपथ-रफी मार्ग क्रॉसिंग, कर्तव्यपथ-जनपथ क्रॉसिंग, कर्तव्यपथ मानसिंह रोड क्रासिंग और कर्तव्यपथ सी हेक्सागन पर सुबह 10.15 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक यातायात प्रतिबंध रहेगा।

### इन रास्तों का करें इस्तेमाल

उत्तर दिल्ली से दक्षिण दिल्ली और दक्षिण दिल्ली से जाने वाले लोग रिंग रोड, सराय काले खां, आइपी फ्लाईओवर, राजघाट, लाजपत राय मार्ग, मथुरा रोड, भैरों रोड, रिंग रोड, अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, कमाल अत्तातुर्क मार्ग, कौटिल्य मार्ग से जा सकते हैं। पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिल्ली की ओर जाने वाले लोग रिंग रोड से वंदे मातरम मार्ग से जा सकते हैं।

इसी तरह विनय मार्ग, शांति पथ या नई दिल्ली और उससे आगे जाने वाले वाहन चालकों को सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, राउंड अबाउट आरएमएल, बाबा खड़क सिंह मार्ग या पार्क स्ट्रीट-मंदिर मार्ग से होते हुए उत्तर दिल्ली या नई दिल्ली की ओर से होकर जाना पड़ेगा।

### गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य विशेषताएं

गणतंत्र दिवस परेड नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सुबह 10:00 बजे से आयोजित की जाएगी। इस वर्ष, परेड शानदार ढंग से कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाली झांकियों से भरी होगी, जो उनकी संबंधित संस्कृतियों, रीति-रिवाजों और उपलब्धियों को दर्शाती हैं। गणतंत्र दिवस का दिन भारत की एकता, विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। वर्ष 1950 में भारतीय संविधान अस्तित्व में आने के बाद से हर साल इसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह राष्ट्र के लिए विविधता में एकता की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। हर साल यह 26 जनवरी को मनाया जाता है।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

# दिल्ली पुलिस जाम से निपटने के लिए शुरू करेगी ये नई पहल, वाहन चालकों को सड़कों पर ट्रैफिक से मिलेगी राहत

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या से जल्द ही निजात मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस बहुत जल्द 92 आधुनिक क्रेन खरीदेगी। फिलहाल पुरानी क्रेनों से वाहनों को उठाने में पुलिस को परेशानी होती है। नई क्रेनों से वाहन चालकों को राहत मिलेगी। पुलिस के पास अगले 4-5 महीने के भीतर ये क्रेन आ जाएंगी। लेख के माध्यम से पढ़िए पूरी खबर।

**नई दिल्ली।** राजधानी में जाम लगातार बड़ी समस्या बनकर उभरता जा रहा है। पार्किंग की समस्या के कारण लोग जहां-तहां अपने वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे जाम लगने के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

आने वाले समय में वाहनों के कारण लगने वाले जाम की समस्या से ट्रैफिक पुलिस जल्द वाहन चालकों को निजात दिला पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस ने 92 माडर्न क्रेन खरीदने का निर्णय किया है। इसके लिए कई माह पहले टेंडर निकाला गया था।

### पुलिस निजी ठेकेदारों से किराए पर लिए क्रेनों का कर रही इस्तेमाल

चार से पांच माह के अंदर रेट लिस्ट लेकर पुलिस क्रेनें खरीद लेगी। अभी ट्रैफिक पुलिस निजी ठेकेदारों से किराए पर लिए गए 76 क्रेनों का इस्तेमाल कर रही हैं। किराए के मद में पुलिस को क्रेन मालिकों को हर माह लाखों रुपये किराया भरना पड़ता है। दिल्ली पुलिस के पास अपनी 20 सरकारी क्रेनें हैं जो वर्षों पुरानी हैं।

जानकारी के मुताबिक, ट्रैफिक पुलिस जिन 76 किराए के क्रेनों का वाहनों को उठाने व वीवीआइपी रूटों पर खड़ी गाड़ियों को उठाने के लिए इस्तेमाल करती हैं उनमें अधिकतर पुरानी हैं। ऐसे में 92 नई माडर्न क्रेनें खरीदने पर ट्रैफिक पुलिस के कामकाज में तेजी आएगी।

### अवैध तरीके से पार्क की गई गाड़ियों को उठाकर वहां से हटाया

जल्द से जल्द पुलिस सड़कों पर अवैध तरीके से पार्क की गई गाड़ियों को उठाकर वहां से हटाया जा सकेगा। महंगी गाड़ियों को उठाने में गाड़ियों के क्षतिग्रस्त हो जाने की समस्या नहीं आएगी। जो नई क्रेनें खरीदी जा रही हैं उनमें 76 ट्रैफिक पुलिस को दी जाएंगी। इनमें 44 पांच टन क्षमता उठाने वाली व 32 तीन टन क्षमता उठाने वाली क्रेनें शामिल हैं।

पुलिस अधिकारी का कहना है जो कंपनी कम रेट तय करेगी उसी से क्रेनें खरीदी जाएंगी। कई करोड़ की लागत से ये क्रेनें खरीदी जा रही हैं। हर साल दिल्ली पुलिस किराए पर लिए गए क्रेनों के मालिकों को करोड़ों रुपये किराया भरती है। अपनी क्रेनें आ जाने से इससे निजात मिलेगा।

### हर रोज एक क्रेन का भरती है तीन हजार रुपये

नई क्रेनों के आ जाने के बाद किराए के सभी क्रेनों को हटा दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस को ठेके पर केवल मजदूरों व चालकों को रखना होगा। क्योंकि किराए के क्रेनों पर मजबूर व चालक, ठेकेदार के ही होते हैं। प्रतिदिन दिल्ली पुलिस एक क्रेन का 3000 किराया भरती है।

ट्रैफिक पुलिस की संख्या करीब 7000 है। दिल्ली में करीब 50 ट्रैफिक सर्किल हैं। प्रत्येक सर्किल में एक-एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं जिनकी देखरेख में जेडो व अन्य कर्मी ट्रैफिक के सुगम संचालन व ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटने की कार्रवाई करते हैं।

# नोएडा एयरपोर्ट से जल्द जुड़ेगा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, रफ्तार भरते दिखेंगे वाहन

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा एयरपोर्ट से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली 31 किलोमीटर लंबी लिंक रोड का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस सड़क के बन जाने से नोएडा ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद के बीच आवाजाही बिल्कुल आसान हो जाएगी। साथ ही हरियाणा से सीधे एयरपोर्ट पर पहुंचा जा सकेगा। एक क्लिक में पढ़िए इससे संबंधित पूरा अपडेट।

**ग्रेटर नोएडा।** एनसीआर में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच आवाजाही के लिए नया विकल्प तैयार हो चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को नोएडा एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी के लिए 31 किमी लंबी लिंक रोड का काम अंतिम चरण में हैं।

बीच में बने पुल और संपर्क रोड को जोड़ने का काम चल रहा है। अप्रैल में एयरपोर्ट के शुरू होने से पहले यह काम पूरा हो जाएगा। लिंक रोड और यमुना एक्सप्रेस (Yamuna Express) वे को जोड़ने को बनाए गए इंटरचेंज का निर्माण पूरा होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से इसकी अनापत्ति के लिए आवेदन किया है।

### इनको मिलेगा लाभ

नोएडा, ग्रेटर नोएडा से फरीदाबाद के लिए अभी दिल्ली होकर या पेरिफेरल एक्सप्रेस वे होकर आवाजाही का विकल्प है। इसमें दूरी व समय अधिक लगता है, लेकिन नोएडा एयरपोर्ट की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी के लिए बल्लभगढ़ से जेवर तक बनाई जा रही लिंक रोड से आवाजाही के लिए एक और विकल्प मिलने जा रहा है।

लिंक रोड से हरियाणा की ओर से सीधे एयरपोर्ट पर पहुंचा जा सकेगा। इसके साथ ही नोएडा ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद के बीच आवाजाही करने वालों के लिए भी रास्ता आसान हो जाएगा। 31 किमी लंबे इस मार्ग का आठ किमी हिस्सा उत्तर प्रदेश व शेष हरियाणा में है।

### एएआई में आवेदन कर इंटरचेंज के लिए मांगी अनापत्ति-NHAI

यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र भाटिया का कहना है कि लिंक रोड के बीच में जगह-जगह पुल बनाए गए हैं। पुल से सड़क को जोड़ने का काम हो रहा है। अप्रैल में एयरपोर्ट शुरू होने से पहले इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। यमुना एक्सप्रेस वे पर एनएचएआई द्वारा दो सौ करोड़ की लागत से बनाए गए हैं।

चार लूप के इंटरचेंज का निर्माण पूरा हो चुका है। एनएचएआई ने एएआई में आवेदन कर इंटरचेंज के लिए अनापत्ति मांगी है। ताकि विमान के मार्ग में इंटरचेंज की ऊंचाई के कारण किसी तरह तरह की तकनीकी बाधा पैदा न हो।

साठ मीटर चौड़ी सड़क से कनेक्टिविटी के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। एयरपोर्ट शुरू होने से पहले साठ मीटर चौड़ी सड़क के दो किमी हिस्से का निर्माण भी पूरा हो जाएगा।

इससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद से आने जाने वाले वाहन सुगमता से एयरपोर्ट तक पहुंच सकेंगे। फरीदाबाद, बल्लभगढ़ से भी नोएडा एयरपोर्ट पहुंचना आसान हो जाएगा।

# दिल्ली टैक्सी एन्ड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने पर्यावरण मंत्री भूपेंदर यादव को कमिसन फॉर एयर क्वाल्टी मैनेजमेंट की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक शिकायत पत्र दिया

परिवहन विशेष न्यूज

**नई दिल्ली।** दिल्ली टैक्सी एन्ड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंदर यादव जी को कमिसन फॉर एयर क्वाल्टी मैनेजमेंट की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक शिकायत पत्र दिया.

टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना हैं की काफी समय से CAQM की दामनकारी नीतियों से दिल्ली एनसीआर के अलावा पूरे भारत के डीजल BS 4 टैक्सी( LMV टेम्पो ट्रैवेलर )चलाने वाले आर्थिक और मानसिक तौर पर लगातार प्रताड़ति हो रहे हैं.

इसके अलावा प्राइवेट कार चलाने वालो का भी यही हाल हैं.

संजय सम्राट का कहना हैं कि दिल्ली के ट्रांसपोर्टर्स करोना महामारी से बचकर बड़ी मुश्किल से अपनी रोजी रोटी चलाने की कोशिश करी है.

लेकिन कमिसन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) ने प्रदूषण के नाम पर हमारी डीजल BS 4 टैक्सी और हलके वाहन टेम्पो ट्रेवलर को बार बार बंद कर रहें है और तो और गरीब टैक्सी वालो पर 20 हजार का जुर्माना भी कर रहें है.

आज तक ना तो (CAQM) कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेन्ट ने और ना ही दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए कोई ठोश नीति बनाई ना ही कोई दूसरे उपाए किये गए है.

जबकि दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश कराने की बात की थी.

सबसे बड़ी बात ये है की CAQM प्रदूषण की आड़ में हमारी डीजल टैक्सीयों को जान भुज कर बंद करवा रहा है. इन्होने जो ग्रेप सिस्टम बनाया है वो ही गलत है. हमारी डीजल BS 4 टैक्सीयों को ग्रेप 3 में रखा गया है, और डीजल BS 2 और BS 3/4 ट्रको को ग्रेप 4 की श्रेणी में. जबकि हमारी ज्यादातर टैक्सीयां जापानी टेक्नोलॉजी की है जो ना के बराबर धुआँ देती है, इसका हमारी गाड़ियों पर प्रदूषण सर्टिफिकेट भी होता है. और ज्यादातर देसी विदेशी पर्यटको को एयर पोर्ट या रेलवे स्टेशन से लेकर दूसरे राज्यों में 10 से 15 दिनों के लिए चली जाती है. जबकि दिल्ली में हजारों की संख्या में ट्रक आते है.

हद तो जब हों जाती है जब CAQM शाम को 5 बजे आर्डर निकाल देता है. उसका नतीजा ये होता है जो टैक्सी सुबह ड्यूटी पर निकली है 2000 रुपये की ड्यूटी के लिए जाती हैं शाम को उसका 20 हजार का जुर्माना दिल्ली ट्रैफिक पुलिस /लोकल दिल्ली पुलिस या दिल्ली एनसीआर के इनफ़ोर्समेंट विभाग द्वारा कर दिया जाता है. जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के अलावा पूरे भारत से दिल्ली एनसीआर में आने वाले टैक्सी वालो का आर्थिक और मानसिक शोषण CAQM और दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है.

संजय सम्राट का कहना हैं की वास्तव में जब सर्दी आती है तो थोड़ा बहुत बदलाव मौसम में होता है. आज तक ना तो दिल्ली सरकार ने और ना ही CAQM ने कभी पूरी तरह कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लगाई ना ही दिल्ली एनसीआर में फैक्ट्रीयों के धुँये पर रोक लगाई ना ही धुल जो हमेशा उड़ती रहती है, दिल्ली एनसीआर में उसके लिए कुछ प्रबंध किये. दिल्ली में रोज हजारों हवाई जहाज रोज आते है ये कितना प्रदूषण करते है इनको रोकने की हिम्मत केंद्र सरकार या CAQM या दिल्ली सरकार ने कभी नहीं करी.

संजय सम्राट ने मांग करी हैं की CAQM आयोग को बंद करा जाए जब तक ये कोई ठोश नीति प्रदूषण पर नहीं बनाता।

# संकष्ट चतुर्थी, तिलकुटा चतुर्थी

साल भर में 12 संकष्टी चतुर्थी व्रत आते हैं। इनमें से कुछ चतुर्थी साल की सबसे बड़ी चौथ में से एक हैं, उनमें से एक है सकट चौथ व्रत। सकट चौथ भगवान गणेश के सबसे महत्वपूर्ण पर्व में से एक है। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सकट चौथ का त्योहार मनाया जाता है।

सकट चौथ व्रत की महिमा से संतान की सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी। भक्तों को सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। सकट चौथ वर्ष की शुरुआत में पड़ता है, इसलिए जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं। उन्हें पूरे वर्ष अनंत सुख, धन, सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

**संकष्ट चतुर्थी की तिथि**

17 जनवरी 2025, शुक्रवार को सकट चौथ है। इसे संकष्टी चतुर्थी, सकट चौथ, तिलकुट चौथ, माघी चौथ, लंबोदर संकष्टी, तिलकुट चतुर्थी और संकटा चौथ आदि नामों से भी जाना जाता है।

माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभः 17 जनवरी 2025, प्रातः 4 बजकर 06 मिनट पर

माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि समाप्तः 18 जनवरी 2025, प्रातः 5 बजकर 30 मिनट पर

**संकष्टी चतुर्थी का महत्व**

संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन की पूजा से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, और घर में सुख-शांति का वातावरण बनता है। इस व्रत को रखने से न केवल संकटों से मुक्ति मिलती है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है।

**संकष्ट चौथ व्रत क्यों किया जाता है?**

सकट चौथ का दिन भगवान गणेश और सकट माता को समर्पित है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों के कल्याण की कामना से व्रत रखती हैं। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इस पूरे दिन व्रत रखा जाता है।

रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। यही कारण है कि सकट चौथ पर चंद्रमा दर्शन और पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन गणपति जी को पूजा में तिल के लड्डू या मिठाई अर्पित करते हैं, साथ में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत पारण करते हैं।

**संकष्ट चौथ की पूजा विधि**

ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत हो जाएं।

इसके बाद सकट चौथ व्रत रखने का संकल्प करें।

एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी और सकट माता की प्रतिमा की स्थापना करें।

सिंदूर का तिलक लगाएं। घी का दीपक जलाएं।

भगवान गणेश की प्रतिमा पर फूल, फल और मिठाइयां अर्पित करें।

पूजा में तिलकुट का भोग जरूर शामिल करें।

गणेश चालीसा का पाठ करें। अंत में बप्पा की आरती करें।

शंखनाद से पूजा पूर्ण करें।

प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करें।

## गुड़ सेवन

गुड़ का सेवन अधिकांश लोग ठंड में ही करते हैं वह भी थोड़ी मात्रा में इस सोच के साथ की ज्यादा गुड़ खाने से नुकसान होता है। इसकी प्रवृति गर्म होती है, लेकिन ये एक गलतफहमी है गुड़ हर मौसम में खाया जा सकता है और पुराना गुड़ हमेशा औषधि के रूप में काम करता है।आयुर्वेद संहिता के अनुसार यह शीघ्र पचने वाला, खून बढ़ाने वाला व भूख बढ़ाने वाला होता है। इसके अतिरिक्त गुड़ से बनी चीजों के खाने से बीमारियों में राहत मिलती है।

- गुड़ में सुक्रोज 59.7 प्रतिशत, ग्लूकोज 21.8 प्रतिशत, खनिज तरल 26प्रतिशत तथा जल अंश 8.86 प्रतिशत मौजूद होते हैं।इसके अलावा गुड़ में कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा और ताम्र तत्व भी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। इसलिए चाहे हर मौसम में आप गुड़ खाना न पसन्द करें लेकिन ठंड में गुड़ जरूर खाएं।

- यह सेलेनियम के साथ एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। गुड़ में मध्यम मात्रा में कैल्शियम, फॉस्फोरस व जस्ता पाया जाता है यही कारण है कि इसका रोजाना सेवन करने वालों का इम्युनिटी पॉवर बढ़ता है। गुड़ में मैग्नेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है इसलिए ये बॉडी को रिचार्ज करता है साथ ही इसे खाने से थकान भी दूर होती है।

- गुड़ और काले तिल के लड्डू खाने से सर्दी में अस्थमा परेशान नहीं करता है। रोजाना गुड़ का सेवन हाइब्लडप्रेशर को कंट्रोल करता है। जिन लोगों को खून की कमी हो उन्हें रोज थोड़ी मात्रा में गुड़ जरूर खाना चाहिए। इससे शरीर में हिमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है।

- गुड़ का हलवा खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। शरीर से जहरीले तत्वों को बाहर निकालता है व सर्दियों में, यह शरीर के तापमान को विनियमित करने में मदद करता है। यह लड़कियों के मासिक धर्म को नियमित करने यह मददगार होता है।

- अगर आप गैस या एसिडिटी से परेशान हैं तो खाने के बाद थोड़ा गुड़ जरूर खाएं ऐसा करने से ये दोनों ही समस्याएं नहीं होती हैं। गुड़, सेंधा नमक, काला नमक मिलाकर चाटने से खट्टी डकारें आना बंद हो जाती हैं।

- ठंड में कई लोगों को कान के दर्द की समस्या होने लगती है। ऐसे में कान में सरसो का तेल डालने से व गुड़ और घी मिलाकर खाने से कान का दर्द ठीक हो जाता है।

# नब दास हत्याकांड मामला राजनीति में लौटा, भाजपा ने बीजद पर उछाला कीचड़

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

**भुबनेश्वर:** कुछ ही दिनों में बीजद के कद्दावर नेता नब दास की हत्या को दो साल हो जाएंगे। 29 जनवरी 2023 को उनकी हत्या कर दी गई। यही कारण है कि उस समय ओडिशा ने राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी थी। क्योंकि हत्या के समय वह ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री थे। मंत्री पर खुलेआम गोलीबारी से उस समय सभी लोग हैरान रह गए।अब एक बार फिर ओडिशा की राजनीति में कीचड़ उछाला जाने लगा है। नबा दास की बेटी और पूर्व विधायक दीपाली दास और उनके भाई हबीब दास सहित भाजपा नेताओं ने आरोपों से इनकार करना जारी रखा है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब भाजपा ने दीपाली किरीमिरा पंचायत समिति की अध्यक्ष अनास्ता को निशाना बनाया। किरीमिरा पंचायत समिति की अध्यक्ष अनास्ता ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने मतदान में धांधली की और उसे रोका, जिसके बाद पार्टी नेता नाराज हो गए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर दीपाली को निशाना बनाया है। भुवनेश्वर एकाम्र विधायक बाबू सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा कि दीपाली अपने पिता की हत्या पर चुप क्यों है। वह सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके बाद दीपाली ने कहा, मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करती हूं कि क्या वह सीबीआई जांच का आदेश दे सकते हैं? उन्होंने पूछा कि क्या वे मेरे परिवार के साथ सहयोग कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे पिता की हत्या का सच सामने आए।दीपाली ने मीडिया से कहा, इसलिए सीबीआई को जांच करने दीजिए। इसके बाद विधायक बाबू सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि अगर दीपाली मुख्यमंत्री से यह मांग करती हैं तो उन्हें आना चाहिए। उन्हें मुख्यमंत्री से मिलकर बताना चाहिए कि सीबीआई जांच चल रही है। बाबू सिंह ने मीडिया से सीधे तौर पर कहा कि अगर वह कहेंगे तो वह उन्हें मुख्यमंत्री के पास ले जाएंगे।

एक कदम आगे बढ़ते हुए कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि दिपाली केवल मीडिया में ही नहीं मनाई जा सकती। उन्हें यह बात मुख्यमंत्री को लिखित में देनी चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्री तय करेंगे कि सीबीआई जांच होगी या नहीं। मंत्री पृथ्वीराज ने कहा कि सीबीआई जांच मीडिया को बताकर नहीं होती। इस मुद्दे पर ओडिशा की राजनीति फिलहाल उथल-पुथल की स्थिति में है।

कुम्भ : सत्य सनातन ज्योति प्रज्वलित!

कुम्भ में सत्य सनातन ज्योति प्रज्वलित,
न कोई ऊंच न नीच सभी हैं प्रफुल्लित।
इंसानी समुन्दर-सा हुआ यह आयोजन,
ये धर्म ध्वजा की पताका फहरे प्रयोजन।
यहाँ कोई किसी को जानता-पहचानता,
हम सबमें हैं आत्मीयतासा भाव जागता।

कुम्भ में सत्य सनातन ज्योति प्रज्वलित,
न कोई ऊंच न नीच सभी हैं प्रफुल्लित।
सही समझ रहें सब एक-दूजे की बोली,
हे प्रयाग संग-संग सभी हुए हमजोली।
आई ये सब के चेहरों पर मुस्कुराहट है,
ये नई सोच नवभारत की एक आभा है।

कुम्भ में सत्य सनातन ज्योति प्रज्वलित,
न कोई ऊंच न नीच सभी हैं प्रफुल्लित।
देश-दुनिया, विदेशी सनातनी को वंदन,
सकारात्मक ऊर्जा दे रहें माथे पे चंदन।
यहीं अपूर्व दिव्य-शक्ति का हैं आकर्षण,
त्रिवेणी तट पर अमृत रसपान विलक्षण।

संजय एम तराणेकर

# केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री का आकांक्षी योजना हेतु सिंहभूम का दौरा सिंहभूम मुख्यतः हो तथा ओड़िया भाषियों का,यह देश का सर्वाधिक कुपोषित

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

**चाईबासा**, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) के तहत 16 से 18 जनवरी 2025 तक झारखंड स्थित देश का सर्वाधिक कुपोषित जिला में से एक पश्चिमी सिंहभूम का तीन दिवसीय दौरा कल से करेंगे। सिंहभूम की पूर्व सांसद गीता कोड़ा सिंहभूम को देश का सर्वाधिक कुपोषित जिला के रूप में लोक सभा में कई बार मामले को उठा चुकी है । देश का सर्वाधिक 60.9% कुपोषित जिला के रूप में यह सदैव चर्चित रहा है ।

सिंहभूम 1957 के पहले पोड़ाहाट राज्य का हिस्सा हुआ करता था । जहां आज भी गांव मे केवल दो भाषाएं हो तथा ओड़िया ही मुलत बोली जाती है । जहां तक इतिहास की बात है 1936 के पहले बिहार ,ओडिशा संयुक्त गृह में 11ओडिया सदस्य होते थे । उसके बाद आजाद भारत में भी बिहार में 1970 तक इस समुदाय का प्रतिनिधित्व होता रहा जहां आज करीब 300 ऑडया विधालय बंद हो चुके हैं , आदिवासी एवं ओडिया जनमानस की विकास को कौन पुछता भला । कांग्रेस सरकार में इसी सिंहभूम के सरायकेला में जन्मे पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री के पी सिंह देव इस क्षेत्र को काफी तजब्बो देते थे । जिसके कारण कांग्रेस का गढ कभी सिंहभूम को कहा जाता था , जहां बागुन सुम्बरुई जैसे नेता लम्बे समय तक रहे हैं । अब देखना बड़ी दिलचस्प होगा कि सिंहभूम के सीमा से महज 26 किलोमीटर दुर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी आते हैं, जहां उसी इलाके में केन्द्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री को क्या प्रतिपुष्टि मिल पाता धरातल से।

गुरुवार शाम तक मंत्री मुर्गन रांची पहुंच चुके है। अपने आगमन पर मंत्री जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बातचीत करेंगे, जिसका उद्देश्य जिले द्वारा हासिल की गई प्रगति पर नज़र रखना है। दौरे के दूसरे दिन माननीय मंत्री जगन्नाथपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और केज फिशरीज-करंजिया का दौरा करेंगे। इसके बाद सेल खदान का साइट विजिट किया जाएगा। ।

यह कार्यक्रम आकांक्षी योजना हेतु किया जा रहा है । बताते चलें कि 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा लंच किए गए 28 राज्यों के 112 कम विकसित जिले शामिल है जहां पश्चिमी सिंहभूम भी है । तीन दिवसीय दौरे का अंतिम दिन जिला अधिकारियों और विभाग प्रमुखों के साथ बातचीत पर केंद्रित होगा, जिसके बाद चाईबासा में एडीपी और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम (एबीपी) के संकेतकों का आकलन करने और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम (एडीपी) के सभी मापदंडों में जिले के विकास को उत्प्रेरित करने के लिए एक समीक्षा बैठक होगी।

कमजोर नागरिकों के उत्थान हेतु परिकल्पित, एडीपी विकास के 81 संकेतकों में मापन योग्य प्रगति पर केंद्रित है, जो स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, और बुनियादी ढाँचा रूपी पाँच महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित है। इस कार्यक्रम का ठोस प्रभाव पड़ा है, जिससे लाखों लोगों के जीवन में सुधार आया है और क्षेत्रीय विषमताओं को दूर किया गया है। सिंघम में देखना दिलचस्प होगा जहां डीएमएफटी फंड विकास का धन नाम पर बोरे न्यारे होते आ रहै हैं । जिले के पांच विधानसभा में एक विधायक को 10 करोड़ जैसी मोटी रकम इसी डी एम एफ टी फंड से मिलता है । जहां उनकी बुनियादी सुविधा आज तक मिल नहीं पाना। शिक्षा से वंचित, यहां तक की कुपोषण जैसी समस्या विकराल रूप लिए हुए है । ऊपर से अविकसित क्षेत्र होने के नाते उग्रवाद जैसी समस्या से जिला जुझ रहा है ।यही वजह है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) 329 जिलों में 500 ब्लॉकों को लक्षित करता है, जहाँ पर 40 संकेतकों में मापी गई आवश्यक सरकारी सेवाओं की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित हो।

दिसंबर 2024 में, मंत्री मुरुगन ने झारखंड के एक अन्य आकांक्षी जिले पलामू की अपनी यात्रा का समापन किया है । यात्रा के दौरान, माननीय मंत्री ने विभागाध्यक्षों और दूरदर्शन, पत्र सूचना ब्यूरो और केंद्रीय संचार ब्यूरो के अधिकारियों के साथ बैठकें की। मंत्री ने सुशासन सप्ताह के हिस्से के रूप में "प्रशासन गांव की ओर" विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला में भी भाग लिया।

# विकास के सपने और हकीकत

विजय गर्ग

भारतवासियों ने बड़ी उम्मीद के साथ इस नए वर्ष का स्वागत किया है। सत्ता ने उन्हें बताया है कि दुनिया में आज भारत का सानी नहीं अंतरिक्ष से लेकर अर्थव्यवस्था तक इसका डंका बज रहा है। कहा जा रहा है कि भारत अपने अतीत को भविष्य में बदल देगा। यानी वह विश्वगुरु था और 'अब फिर बन फिर बन जाएगा। वैसे भी अब 'जय जवान जय किसान' से 'जय अनुसंधान' हो गया है। देश तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का महत्त्व इतना बढ़ गया है कि उसकी । उपेक्षा नहीं की जा जा सकती। मगर अपना प्रशस्ति गान करने के इस दंभ में कुछ चुनौतियां भी देश की अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी हो गई हैं। ये पहले से शुरू हो गई थीं और सिवाय मंचीय भाषणों और दावों के, इन समस्याओं को हल करने का कभी गंभीर प्रयास नहीं किया गया। भूख मिटाने की गारंटी तो दे दी, लेकिन देश के बेकार हाथों को काम देने की गारंटी नहीं दी। देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई, लेकिन उसके लिए कच्चे माल और ऊर्जा ऊर्जा स्रोतों का सृजन भारत में । आजादी का अमृत महोत्सव' मनाया गया। महोत्सव के बाद हुई कि अब त्वरित गति से पूंजी निर्माण होगा। इसके साथ ही देश में बुनियादी उद्योगों की ऐसी नींव डाली जाएगी कि फुटकर उद्योगों को अपना रास्ता पकड़ने में कठिनाई नहीं होगी। दुनिया में भारत की आबादी सभी देशों से अधिक हो गई है। इस आबादी को काम देने के लिए सहकारी आंदोलन 1 को नया जीवन देने की घोषणा संसद में बार- बार होती रही। मगर अभी तक यह सहकारी आंदोलन अपने पुराने भ्रष्टाचारों के आतंक से बाहर नहीं आ सका है। बार-बार एक लाख जवानों को राजनीति में लाने की बात हुई, लेकिन नजर आया कि देश र के नाम पर परिवारवाद ही प्रोत्साहित हो रहा है।

देश नौजवानों की रगों में नए में नहीं हुआ।

आज वर्ष की एक सार्थक के शुरुआत करने की बात कहनी हो, हमें देश के बुनियादी उद्योगों का सबल विकास, नींव के रूप में बनाने पर चर्चा करनी' चाहिए, लेकिन पहला सवाल यही है कि बीते नवंबर में देश के आठ बुनियादी उद्योगों में उत्पादन धीमा कैसे हो गया। आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि यह 4.3 फीसद रहा। एक साल पहले यह 7.9 फीसद था ऐसा क्यों हुआ ? क्योंकि हमारा सपना तो दुनिया की पांचवीं आर्थिक महाशक्ति से आगे बढ़ कर तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनना है। मगर नवंबर 2024 कहता बीत गया कि कच्चे तेल गैस के उत्पादन में कमी आई है। कोयला, रिफाइनरी

और प्राकृतिक उत्पाद, उर्वरक, इस्पात और बिजली के उत्पादन में वृद्धि के बजाय कमी नजर आने लगी है। सबसे अधिक कमी कोयला उत्पादन में आई है, कोई 7.5 फीसद जबकि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा की बहुत बातें होती हैं। इसके उपयोग के लिए तैयार होने वालों के लिए कुछ प्रोत्साहन भी घोषित किए गए हैं, लेकिन इस देश में लोग आज भी कोयले को ही ताप और ऊर्जा का बड़ा साधन मानते हैं।

जब इन मूल उद्योगों के उत्पादन की ओर पिछले वर्ष के आंकड़ों को जांचते हैं, तो पाते हैं कि

तुलनात्मक ढंग से आज की तुलना में तब इन सभी बुनियादी उद्योगों में विकास की गति अधिक थी। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि इस वर्ष अप्रैल-नवंबर के दौरान बुनियादी ढांचे की वृद्धि दर 4.2 फीसद रही। जबकि पिछले वित्तवर्ष में यह 8.7 फीसद थी। बुनियादी ढांचे के विकास को इतनी बड़ी ठोकर क्यों लगी ? इसका कारण है कि निवेशक और उद्योगपति अपने हर निवेश से त्वरित लाभ की आशा करते हैं, लेकिन देश का बुनियादी ढांचा तो केवल भावी उत्पादन का आधार बनता है। देश के विकास का ठोस धरातल बनता है इसलिए तत्काल लाभ न मिलने की वास्तविकता के कारण निजी निवेशक इस ओर पैसा नहीं लगाना चाहते वादे के बावजूद सरकार पूंजी निर्माण और बुनियादी उद्योगों के विकास के लिए अतिरिक्त राशि नहीं निकाल पाती। जहां तक अनुसंधान का संबंध है, हमने 'जय अनुसंधान' न' तो कह दिया, लेकिन दूसरी महाशक्तियों के मुकाब

अनुसंधान के लिए व्यय उनसे तीन-चार गुना कम है। इसके लिए गंभीर प्रयास भी नजर नहीं आते। अंततः इसका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय व्यापार में देश की साख पर पड़ता है।

हम अपने दवा उत्पादन क्षेत्र पर बहुत गर्वित होते रहे हैं। जब कई दावों के बाद दुनिया में दवाओं और अन्य संबंधित वस्तुओं का निर्यात बढ़ा, तो पता चला कि यहां स्तरहीन दवाओं का निर्माण हो रहा है। नकली दवाएं भी खूब बन रहीं। बाद में देश को मिले निर्यात के आदेश निरस्त होने लगे। दवाएं वापस आकर देश के निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनने के सपनों को झुठलाने लगीं। केवल दवाएं ही क्यों, हमने जो माल इस देश से निर्यात किया, वह अधिक लागत वाला माना गया। इसके लिए विदेशों से निर्यात के वो आदेश हमें नहीं मिले, जिसकी हमें । उम्मीद थी। अधिकतर पैसा तेजी से विकसित होते कुछ देशों की ओर चला गया। आप देखिए कि दुबई में भारतीयों ने कितना पैसा लगाया क्योंकि वहां व्यापार की सहजता और सुलभता है। ऐसा तीसरी दुनिया के अन्य कई देशों में भी है।

भारत कार्य व्यापार के दावों को सहज करने के बावजूद नौकरशाही और लालफीताशाही की नाक में नकेल नहीं डाल सका। अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षक बताते हैं कि सुधार के दावे तो बहुत किए गए, लेकिन उत्पादन हर चरण पर इजाजत का ऐसा चक्रव्यूह व्यापारियों को झेलना पड़ता था कि उन्होंने भी उन देशों का रुख करना शुरू कर दिया, जहां नियम कायदों का यह तंत्र जाल नहीं था। तंत्र के हर मोड़ पर भ्रष्ट अधिकारी अपना मुंह खोले बैठे थे। नया युग लाना है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दुविधा यही है कि हमारी मुद्रा डालर के मुकाबले लगातार गिरती जा रही है और हमारे स्वर्ण भंडार का का क्षरण हो रहा है। इस समय डालर मुकाबले रुपया 86 रुपए प्रति डालर से ऊपर चला गया है। इस गिरावट को थामने के लिए हम वैकल्पिक मुद्रा भी प्रयोग नहीं कर सकते, जैसा ब्रिक्स सम्मेलन म्मेलन के दौरान सोचा गया था।

दूसरी ओर, बचत के पारंपरिक तरीके सोने की तेजी को छू नहीं पा रहे। चांदी भी लगातार तेज हो रही है। देश में आर्थिक सुरक्षा के लिए सोने का संग्रह करना पुरानी रिवायत है। सोने के पीछे बौराई जनता उसे इस नए आर्थिक वर्ष में 90 हजार रुपए प्रति तोला तक ले जा सकती है। अभी यह अस्सी हजार पार करने को बेताब है। यह न भूलें कि सोने का अपने देश में उत्पादन बहुत कम है। मुख्यतः सोना भी आयात किया जाता है। अब अगर आर्थिक सुरक्षा की तलाश में देशवासी सोने-चांदी जमा करने के लिए भागते हैं, तो अंदाजा लगाइए कि इन मूल्यवान धातुओं के आयात से हमारी आयात व्यवस्था कैसे गड़बड़ा जाएगी और जिस देश को हम निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की बार-बार घोषणा करते हैं, क्या यह घोषणा मात्र एक सपना ही रहेगी ?

**सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब**

# सलमान खान पर फायरिंग, बाबा शिद्धकी की हत्या और अब सैफ अली खान पर हमला बताता है कि भाजपा की सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम हैं : केजरीवाल

सुषमा रानी

**नई दिल्ली,** आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली समेत पूरे देश में लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम भाजपा पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में जब सेलीब्रिटीज सुरक्षित नहीं हैं तो एक आम आदमी की सुरक्षा की बात ही क्या की जाए? सलमान खान पर फायरिंग, बाबा शिद्धकी की हत्या के बाद अब सैफ अली खान पर जानलेवा हमला यह बताता है कि भाजपा की सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम हैं। भाजपा दिल्ली को भी सुरक्षा नहीं दे पा रही है। दिल्ली में रोज हत्याएं हो रही हैं, व्यापारियों को वसूली की धमकी आ रही है। भाजपा से देश के बॉर्डर की सुरक्षा भी नहीं हो रही है। ये रोज कहते हैं कि सीमा पार करके रोहिंग्या आ रहे हैं। इनकी डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। अब इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि बुधवार की रात कुछ अज्ञात लोगों ने देश के प्रसिद्ध अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर 6 बार चाकुओं से हमला किया। पता चला है कि उनका अस्पताल में इलाज जारी है। हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लेकिन यह बेहद चिंताजनक बात है कि इतने बड़े एक्टर की सुरक्षा ऐसी नहीं होगी कि कोई खिड़की से उनके घर में घुस गया। इतनी ज्यादा सुरक्षित जगह पर रहने वाले अभिनेता के घर में रात को कोई घुसकर चाकुओं से हमला कर दे तो यह वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब है कि दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं।

उन्होंने कहा कि मुंबई के अंदर यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले अभिनेता सलमान खान के घर पर शूट आउट हुआ था। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी एनडीए के पार्टनर थे। उनकी दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। अगर देश के इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं हैं, अगर इतने बड़े सेलिब्रिटीज को भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती है तो एक आम आदमी की सुरक्षा की क्या ही बात की जाए? चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि गुजरात की जेल में बैठकर एक गैंगस्टर खुलेआम फिरौती और शूट आउट के आदेश दे रहा है। देशभर में अन्य गैंगस्टर्स खुलेआम अपना-अपना राज चला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अपराधियों की मौजूदा सरकारों के अंदर अच्छी खासी पैठ है। अपराधी धड़ल्ले से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें पकड़े जाने का कोई डर नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें ऊपर से पूरा संरक्षण हैं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ना केवल लोगों को सुरक्षा देने में असमर्थ है, बल्कि इनसे देश की सीमाओं की सुरक्षा भी नहीं हो रही है। ये रोज कहते हैं कि इनसे इंडो-बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा नहीं हो रही है। ये रोज चिल्लाते हैं कि रोहिंग्या सीमा पार करके आ रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? अगर इनसे बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही है तो इस्तीफा दे दें। किसी भी सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी अपने बॉर्डर की सुरक्षा करनी होती है। अगर कोई सरकार खुलेआम मान रही है कि उनसे बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही है तो उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनसे देश के सेलिब्रिटीज की सुरक्षा नहीं हो रही है। इनसे देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है। इनसे देश की राजधानी की सुरक्षा नहीं हो रही है

उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में खुलेआम सड़कों पर गैंगवॉर चल रहे हैं। खुलेआम 20-25 राउंड फायरिंग हो रही है। हर दूसरे दिन व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं। व्यापारियों से कहा जा रहा है कि इतने करोड़ रुपए पहुंचा दो वरना तुम्हें मार डालेंगे। दिल्ली में व्यापारी, महिलाएं और यहां तक कि बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली से रोज 17 बच्चे गायब हो रहे हैं। ये दिल्ली को सुरक्षा नहीं दे सकते। ये देश के सेलिब्रिटीज को सुरक्षा नहीं दे सकते। ये देश के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते। ये देश की सीमाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते। इसलिए आज डबल इंजन की सरकार ना ही अच्छी सरकार दे सकती हैं और ना ही देश को सुरक्षा दे सकती हैं। दिल्ली में 2013 की तुलना में आज चार गुना अपराध बढ़ गया है

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम अभिनेता सैफ अली खान के ऊपर हुए कातिलाना हमले की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि हर वक्त गंदी राजनीति करना बंद करो। राजनीति के अलावा अपने काम करो। जनता ने आपको चुनकर भेजा है और आप पर भरोसा किया है। इसलिए जनता ने जो काम आपको दिए हैं, उन्हें करो। किसी भी सरकार का सबसे पहला काम सुरक्षा देना होता है और दूसरा न्याय देना होता है। ये सुरक्षा देने में असमर्थ हो रहे हैं। इन्होंने दिन पर दिन देश का माहौल खराब कर दिया है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि आप काम करना शुरू करो और गंदी राजनीति करना बंद करो।

# मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जनता की सेवा का प्रण लेते हुए अपना नामांकन दाखिल किया- मनीष सिसोदिया

सुषमा रानी

**नई दिल्ली,** आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को जंगपुरा विधानसभा सीट से अपना नामांकन कर दिया। नामांकन से पहले वह कालकाजी मंदिर पहुंचे और कालका माई से आशीर्वाद लिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जनता की सेवा का प्रण लेते हुए जंगपुरा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। मेरा यह नामांकन अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की राजनीति की दिशा में बढ़ाया एक और कदम है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह पिछले 10 साल से दिल्ली भर में अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम को प्यार, सम्मान और आशीर्वाद मिला है, वह इस चुनाव में भी बरकरार रहेगा।

मनीष सिसोदिया ने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि मैंने आज जंगपुरा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और अरविंद केजरीवाल के एक सिपाही के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। मुझे विश्वास है कि जंगपुरा के लोग वही प्यार और सम्मान अपने इस भाई को देंगे जो वह पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी को देते रहे हैं। पूरी दिल्ली में जो प्यार, सम्मान और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम को मिलता रहा है, वही प्यार और सम्मान इस चुनाव में भी बरकरार रहेगा। मैं जंगपुरा के विधायक के रूप में चुने जाने पर जंगपुरा के लोगों के लिए उनके सुख-दुख में साथ दे सकूं और शिक्षा व स्वास्थ्य के माध्यम से उनके भविष्य के निर्माण में सहयोग कर सकूं, इसी भावना के साथ मैंने नामांकन किया है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं जंगपुरा से एक उम्मीदवार के रूप में जंगपुरा के लोगों के बीच में जा रहा हूं।

वहीं, मनीष सिसोदिया ने नामांकन दाखिल करने के बाद अपने एक्स हैंडल पर कहा कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जनता की सेवा का प्रण लेते हुए आज जंगपुरा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। मेरा यह नामांकन अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की राजनीति की दिशा में बढ़ाया एक और कदम है।

**घर से दही-चीनी खाकर नामांकन के लिए निकले नामांकन से पहले कालकाजी मंदिर के किए दर्शन**

# विकास के नाम पर जनता को ठगा गया है: डॉ एम यूं दुआ

सुषमा रानी

राष्ट्रीय महागठबंधन ने प्रेस वार्ता साधा निशाना

**नई दिल्ली:** राष्ट्रीय महागठबंधन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने 50 प्रत्याशी उतारे हैं जिसकी घोषणा आज एहरा नेशनल पार्टी के केंद्रीय कार्यालय लक्ष्मी नगर, दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में की गई ।

घोषणा करते हुए एहरा नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ एम यू दुआ ने कहा कि दिल्ली, भारत की राजधानी और एक ऐतिहासिक शहर, अपनी अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत और विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जानी जाती है ।लेकिन आम आदमी पार्टी इस शहर की स्थिति ख़राब कर दी है, दिल्ली का हर वर्ग इस सरकार से परेशान है, विकास के नाम पर सिर्फ़ झूठे वादे मिले हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ा संकट है। कई बार वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है, जिससे सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं।

दिल्ली में पानी की उपलब्धता एक और प्रमुख समस्या है। यमुना नदी प्रदूषित है, सफाई के नाम पर सिर्फ़ जुमले मिले हैं।

दिल्ली में यातायात जाम आम बात हो गई है। जिसकी वजह से जनता नाराज़ है।

दिल्ली की स्वास्थ सेवाओं पर बात करते हुए डॉ दुआ ने कहा कि दिल्ली में आम लोगों का स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच अब भी चुनौतीपूर्ण है। सरकारी अस्पतालों में भीड़ और निजी अस्पतालों की महंगी सेवाएं गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी समस्या हैं और मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ एक धोखा है और करप्शन का अड्डा है।

आम आदमी पार्टी जो करप्शन के खिलाफ़ आई थी आज पूरी तरह से करप्शन में डूब गई है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में गरीब वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अब भी चुनौती है। लेकिन यह दलित बच्चों पी एच डी के लिए बाहर भेजना चाहते हैं जो एक धोखा है।

साथ ही, बढ़ती बेरोजगारी युवाओं के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है और अब जीत के लिए मुफ़्त रेवड़ियों का सहारा ले रही है।

उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों ने हमेशा जनता के साथ धोखा किया है ।इस लिए अब एक विकल्प की आवश्यकता है और उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प एहरा नेशनल पार्टी है ।यह समय है कि हम दिल्ली को एक स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित शहर बनाने के लिए एकजुट हों।

# ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से बिना स्वीकृति लिए केजरीवाल की गिरफ्तारी की थी

सुषमा रानी

**नई दिल्ली,** आम आदमी पार्टी ने तथाकथित शराब घोटाले में ईडी द्वारा तीन साल बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय से स्वीकृति लेने पर भाजपा पर करारा हमला बोला है। ''आप'' के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह का कहना है कि देश के सामने एक बार फिर साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी और अवैध थी। ईडी ने गृह मंत्रालय से बिना स्वीकृति लिए गिरफ्तारी की थी, जबकि एजेंसियों को स्वीकृति लेनी होती है। उन्होंने कहा कि भाजपा, प्रधानमंत्री और अमित शाह ने राजनीतिक दुर्भावना के तहत तथाकथित शराब घोटाला मनगढ़ंत बनाया था। तीन साल बाद स्वीकृति लेने से साफ हो जाता है कि यह पूरा मामला ही फर्जी है।

गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर संजय सिंह ने कहा कि बुधवार को साबित हो गया कि तथाकथित शराब घोटाला भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा बनाया गया एक मनगढ़ंत घोटाला था। इस पूरे मामले का कोई सिर-पैर नहीं था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह अवैध और गलत थी। मनीष सिसोदिया और मेरी गिरफ्तारी भी पूरी तरह से फर्जी और अवैध थी। ये लोग तीन साल से झूठा मामला चला रहे हैं, जिसमें इन्होंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और मुझे गिरफ्तार कर लिया। इन्हें तीन साल बाद याद आ रहा है कि इस मामले में स्वीकृति भी लेना है। इसका मतलब है कि पूरा मामला फर्जी है और सारी गिरफ्तारी अवैध थीं।

उन्होंने कहा कि इन्होंने एक मुख्यमंत्री को बिना किसी प्रमाण और स्वीकृति के गिरफ्तार किया। इस देश में यह क्या हो रहा है। यह अपने आप में बहुत चौंका देने वाली बात है कि ईडी ने बगैर स्वीकृति के एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की। इसका मतलब है कि इस पूरे मामले को भाजपा और पीएम मोदी द्वारा फर्जी तरीके से तैयार कराया गया। अगर जरा भी शर्म है तो इस अपराध के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक रूप से अरविंद केजरीवाल से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अपराध किया है। इस बात के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए।

संजय सिंह ने कहा कि मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह पूरा मामला राजनीतिक दुर्भावना के कारण बनाया गया था। इसमें कोई सत्यता नहीं थी और आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध थी। एजेंसियों को स्वीकृति लेने की जरूरत होती ही है। क्या एक मुख्यमंत्री को बगैर स्वीकृति के गिरफ्तार किया जा सकता है? यह अपने आप में ही सामान्य बात नहीं लगती है।

# '300 यूनिट बिजली मुफ्त, 500 में सिलेंडर और राशन किट फ्री', चुनाव से पहले कांग्रेस ने दी दो और गारंटी

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक और गारंटी का दावा किया है। कांग्रेस ने दावा किया कि आप की 200 यूनिट के मुकाबले कांग्रेस फ्री बिजली योजना के तहत लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। महंगाई मुक्ति योजना के तहत 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा और साथ में राशन किट भी फ्री दी जाएगी।

**नई दिल्ली।** दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक और गारंटी का दावा किया है। कांग्रेस ने दावा किया कि आप की 200 यूनिट के मुकाबले कांग्रेस फ्री बिजली योजना के तहत लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।

**500 रुपये में सिलेंडर देने का किया वादा**

महंगाई मुक्ति योजना के तहत 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा और साथ में राशन किट भी फ्री दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान तेलंगाना के सीएम रेमंत रेड्डी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एक साथ कांग्रेस की चौथी और पांचवीं गारंटी दी।

कहा कि अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी तो दिल्ली वासियों को 400 यूनिट तक बिजली के उपयोग का कोई पैसा नहीं देना होगा।

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी काजी निजामुद्दीन और प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे।

**सीएम भगवंत मान ने किया रोड शो**

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बृहस्पतिवार को गांधी नगर और घोंडा विधानसभा में आम आदमी पार्टी (आप) प्रत्याशियों के लिए रोड शो किया। मान ने कांग्रेस और भाजपा पर हमला बोला।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस टाइम वेस्ट है। इनका जीरो का रिकॉर्ड इस बार भी कायम रहेगा। इनके नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खरगे जहां रहते हैं, वहां के विधायक अरविंद केजरीवाल हैं। इन नेताओं के माली, रसोइये भी इनको वोट नहीं देते होंगे। वहीं भाजपा गली-गलौज वाली पार्टी है। इनके नेता गाली देते हैं, क्योंकि उनको बोलना ही नहीं आता।

आरोप लगाया कि भाजपा के प्रवेश वर्मा जूते, कैश, जैकेट और सोने की चेन सरेआम बांट रहे हैं। इनको लगता है ये लोगों को खरीद लेंगे, लेकिन दिल्ली के लोग स्याने हैं, इन्हें खरीदा नहीं जा सकता। मोदी दूसरों को आप-दा कहते हैं, वह अपना ध्यान दें। भाजपा समाज को बांटने का काम करती है। विकास की बात नहीं करती।

भगवंत मान ने कहा कि आप काम की राजनीति करती है। दिल्ली में हमारी पार्टी ने स्कूलों की कायापलट कर दी। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कर दीं। बिजली-पानी मुफ्त कर दिया। महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर दी। एक दीये से ही दूसरे दीये को ज्योत मिलती है।

यही काम आप ने पंजाब में कर दिया। वहां 850 मोहल्ला क्लीनिक बनाए गए। 50 हजार युवाओं को नौकरियां दीं। ऐसे में उनको चुनें तो आपके दुख दर्द को समझे। पांच फरवरी को फैसला करना है कि अगले पांच साल के लिए आपके परिवार और बच्चों की किस्मत किसके हाथ में हो।

# आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, हमारे के पास नैरेटिव है, नेता है और नीयत है- सौरभ भारद्वाज

सुषमा रानी

**नई दिल्ली।** दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय ने गुरुवार को अपना नामांकन कर दिया। सौरभ भारद्वाज ने ग्रेटर कैलाश तो गोपाल राय ने बाबरपुर विधानसभा सीट से पर्चा भरा है। नामांकन के बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी पार्टी के पास नैरेटिव है, नेता है और नीयत है। जबकि भाजपा के पास दिल्ली चुनाव के लिए कोई एजेंडा नहीं है। वह सिर्फ गाली-गलौज करके, डरा-धमका कर और चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ना चाहती है। उधर गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले लिया है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी पार्टी के पास नैरेटिव है, नेता है और नीयत है। भाजपा के पास चुनाव के लिए कोई एजेंडा नहीं है। वह सिर्फ गाली-गलौज करके, डरा-धमका कर और चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके चुनाव जीतना चाहती है, जो मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पैसे, साड़ियां, बेडशीट और जूते बांट रहा है, तो यह तो सीधा-सीधा आपराधिक कृत्य है। आचार संहिता के तहत इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। वरना हर बाहुबली लाखों-करोड़ों रुपए बांट कर चुनाव जीत जाएगा। उस पर एक एफआईआर करने से क्या होगा? चुनाव आयोग को प्रवेश वर्मा के उपर एक्शन लेना चाहिए, जैसे टीएन शेषन लिया करते थे। चुनाव आयोग को तुरंत प्रभाव से प्रवेश वर्मा को अयोग्य घोषित करना चाहिए। वरना यह माना जाएगा कि चुनाव आयोग भाजपा की मदद कर रहा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ग्रेटर कैलाश में लोग काफी ज्यादा उत्सुक हैं। भाजपा रोज नया चेहरा चलाती है। मंगलवार तक मीनाक्षी लेखी का नाम चल रहा था। फिर स्मृति ईरानी का नाम चलने लगा। बुधवार को कोई कह रहा था कि रोहन जेटली चुनाव लड़ेंगे। मुझे नहीं पता कि कौन चुनाव लड़ेगा लेकिन हम चाहते हैं कि कोई बड़ा चेहरा चुनाव लड़े। क्योंकि कोई बड़ा चेहरा आएगा तो मीडिया हमारा इंटरव्यू लेने आती रहेगी। इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम अपनी जीत को लेकर जनता की तरफ से आश्वस्त हैं। जनता बहुत कुछ नहीं चाहती है। लोगों को यह गलतफहमी है कि जनता पता नहीं क्या चाहती है? जनता आपकी परेशानियां भी समझती है। जहां भी शहर होंगे, वहां पानी, बिजली और सड़कों के मसले हमेशा रहते हैं। मसले आते हैं और वह हल भी होते हैं। जनता चाहती है कि उनका विधायक उनकी परेशानियों को सुने और उनका समाधान करे।

उधर, नामांकन के बाद गोपाल राय ने कहा कि पूरी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बाबरपुर की जनता ने काम के लिए फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाने का संकल्प ले लिया है। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि दिल्ली के हर परिवार की बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के लिए लड़ाई है। बाबरपुर की जनता ने इस बार अरविंद केजरीवाल की विकास की राजनीति को चुनने का मन बना चुकी है। दिल्ली के लोगों के दिल में एक बात बैठी हुई है कि उन्हें एक काम करने वाली सरकार चाहिए। इसलिए उन्हें केजरीवाल को एक बार फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है।

गोपाल राय ने कहा कि बाबरपुर विधानसभा के लोगों ने मुझे काम करने का दो बार मौका दिया, उन सभी को दिल से शुक्रिया करता हूँ। इस बार भी लोगों के अंदर मेरे द्वारा किए गए काम के प्रति समर्थन है और वे चाहते हैं कि इस बार भी उनके विधानसभा से काम करने वाले विधायक को जिताया जाए। 5 फरवरी को हमें बाबरपुर विधानसभा में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट देकर बहुमत से जिताना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने हमें सेवा करने का मौका दिया है और इस बार भी वे आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए संकल्पित हैं। दिल्ली के लोगों का प्यार हमें पहले भी मिलता रहा है और इस बार भी मिलेगा। दिल्ली के लोगों को काम करने वाली सरकार बनानी है और दिल्लीवालों के मन में अरविंद केजरीवाल हैं। नामांकन से पहले सौरभ भारद्वाज ने अपने गांव के प्राचीन शिव मंदिर और प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कालका मां हमारे गांव की इष्टदेवी हैं। हमारे यहां हर बड़ा और शुभ काम कालका माई के नाम से शुरु होता है। इसलिए आज हम कालकाजी मंदिर में मां का आशीर्वाद लेने के लिए आए है और इसके बाद मैं अपना नामांकन दाखिल करुंगा। मेरी प्रार्थना है कि कालका माई का आशीर्वाद हम पर, हमारे गांव पर और दिल्ली पर बना रहे।

मां का हर बच्चा पूरे आत्मविश्वास में रहता है क्योंकि करने वाली कालका मां हैं, वही सब करती हैं।

# नोएडा एयरपोर्ट पर पूरा हुआ तीन सुविधाओं का काम, योगी सरकार ने मानी सभी शर्तें; उड़ान पर क्या अपडेट?

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुबंध की सभी शर्तों को पूरा कर दिया है। बिजली पानी और सड़क कनेक्टिविटी की सुविधाएं एयरपोर्ट की चारदीवारी तक पहुंच चुकी हैं। विकासकर्ता कंपनी अब परिसर के अंदर का ढांचा विकसित करने की जिम्मेदारी संभालेगी। आगे विस्तार से पढ़िए आखिर एयरपोर्ट को लेकर और क्या-क्या अपडेट है।

**ग्रेटर नोएडा।** नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने से पहले प्रदेश सरकार ने अनुबंध की शर्तों को पूरा कर दिया है। एयरपोर्ट की विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. और प्रदेश सरकार के बीच हुए अनुबंध के तहत बिजली, पानी और सड़क कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जानी थी।

**एयरपोर्ट की चारदीवारी तक पहुंच चुकीं तीनों सुविधाएं**

बताया गया कि तीनों सुविधाएं एयरपोर्ट की चारदीवारी तक पहुंच चुकी हैं। परिसर के अंदर का ढांचा विकसित करने की जिम्मेदारी विकासकर्ता कंपनी की है।

**प्रदेश सरकार ने पूरी की अनुबंध की शर्तें**

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास एवं संचालन के लिए प्रदेश सरकार और विकासकर्ता कंपनी के बीच 2021 में अनुबंध हुआ था। इसके तहत प्रदेश सरकार ने बिजली, पानी एवं यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का वादा किया गया था। तीनों ही ढांचागत सुविधाओं का काम एयरपोर्ट शुरू होने से करीब तीन माह पहले ही पूरा कर लिया गया है।

(फलैदा बांगर गांव में रेनीवेल का निरीक्षण करने पहुंचे यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र भाटिया। सौ. प्राधिकरण)

**सेक्टर 32 से एयरपोर्ट को बिजली की आपूर्ति**

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चार चरण में विकसित होगा। यात्रियों की संख्या जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी, एयरपोर्ट के विस्तार का काम शुरू हो जाएगा। शुरुआती चरण में एयरपोर्ट की बिजली जरूरत 19 मेगावाट का आंकलन है। बिजली आपूर्ति के लिए सेक्टर 32 में 400 केवी सब स्टेशन से एयरपोर्ट की बिजली जरूरत को पूरा कर दिया गया है। आपात स्थिति में सेक्टर 18 स्थित 220 केवी सब स्टेशन से भी एयरपोर्ट को बिजली आपूर्ति प्रदान की जा सकेगी।

**रेनीवेल से पानी की आपूर्ति शुरू**

नोएडा एयरपोर्ट की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए यमुना नदी के किनारे रेनीवेल बनाए गए हैं। चार एमएलडी क्षमता का एक रेनीवेल तैयार होने के बाद पानी आपूर्ति शुरू हो चुकी है। चार एमएलडी क्षमता का एक दूसरा रेनीवेल का निर्माण जल्द शुरू होगा। रेनीवेल व पाइप लाइन के निर्माण पर कुल 12.69 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

**क्या बोले नोडल अफसर**

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की विकासकर्ता कंपनी व प्रदेश सरकार के बीच हुए अनुबंध के तहत बिजली, पानी व सड़क कनेक्टिविटी की सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं। एयरपोर्ट परिसर में पानी, बिजली पहुंचाने के साथ सड़क से जोड़ दिया गया है। - शैलेंद्र भाटिया, नोडल अफसर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

## 'मुझे भगवान बुला रहे हैं', चिट्ठी लिख घर से गायब हुआ नाबालिग; अब पुलिस कर रही तलाश

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 से एक 14 वर्षीय किशोर रहस्यमय ढंग से लापता हो गया है। घर से जाने से पहले उसने एक पत्र लिखा है जिसमें उसने लिखा है कि उसे ऐसा लगा कि भगवान उसे बुला रहे हैं। पुलिस ने किशोर की तलाश शुरू कर दी है।

**ग्रेटर नोएडा।** बीटा दो कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर 36 में सोमवार को एक युवक घर से लापता हो गया। घर से जाने से पहले युवक ने एक पत्र लिखा है। जिसे देखकर परिवार के होश उड़ गए।

रोते-विलकते स्वजन पत्र लेकर कोतवाली की तरफ दौड़े। पीड़िता मा ने कोतवाल को पत्र दिखाते हुए गुहार लगाई है। कोतवाली प्रभारी विद्युत गोयल ने बताया कि ममता पत्नी एफ-61 सेक्टर 36 में रहती है। उसका बेटा गगन रविवार की सुबह घर से अचानक लापता हो गया। घर में वह एक पत्र छोड़कर गया है जिसमें लिखकर गया है कि मुझे ऐसा लगा कि खुद भगवान मुझे बुला रहे है।

**'मैं खुद को काबू नही कर सका'**

मैं अपने आपको काबू न कर सका और भगवान के स्थान पर जा रहा हूं। मुझे ढूंढने की कोशिश न करें। पीड़िता ने बताया कि मेरे बेटे की उम्र लगभग 14 वर्ष है। तहरीर के आधार पर पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर किशोर की तलाश कर रही है।

वहीं पर दूसरे मामले में ईकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र स्थित बालक इंटर कालेज के हास्टल से चार छात्र बुधवार की सुबह लापता हो गए। सूचना पर स्कूल में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में स्वजन व पुलिस को सूचना दी गई। पीड़ित स्वजन ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है।

**पुलिस छात्र की तलाश में जुटी**

पुलिस छात्रों की तलाश में है। स्कूल प्रबंधन का दावा है कि छात्र पहले भी ऐसे ही लापता हो चुके हैं। ईकोटेक तीन में खेड़ा चौगानपुर के पास बालक इंटर कालेज है। बसपा शासनकाल से संचालित इस स्कूल में बच्चे हास्टल में रहकर पढ़ते हैं।

चारों छात्र कक्षा 11वीं के हैं। सूचना पर पीड़ित स्वजन भी स्कूल पहुंच गए। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि चारों बच्चे पूर्व में भी स्कूल के हास्टल से भाग चुके हैं। फिलहाल पुलिस बच्चों की तलाश कर रही है।

एक और केस में लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र जेडी स्कूल के सामने रेलवे लाइन के किनारे संदिग्ध हालात में बुधवार शाम दो युवक घायल अवस्था में मिले। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाकर देखा तो एक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल था।

**एक की मौत, दूसरा घायल**

उसका दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक, लोनी बॉर्डर थाने की संगम विहार चौकी क्षेत्र में जेडी स्कूल के सामने रेलवे लाइन के किनारे बुधवार शाम करीब 3:15 बजे दो युवक घायल अवस्था में मिले। एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल था।

पुलिस ने लोनी के संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। मृतक की शिनाख्त मोहम्मद नईम उर्फ रेहान निवासी बदरपुर साउथ दिल्ली के रूप में हुई है। हाल में वह इकराम नगर लोनी में अपने भाई नदीम के पास रहता था। आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान आरिफ निवासी मुस्तफाबाद लोनी के रूप में हुई है।

## पत्नी से झगड़े के बाद तनाव में आया वीडियो क्रिएटर, गंगनहर में कूदा युवक; नहीं मिला कोई सुराग

गाजियाबाद के मोदीनगर में एक युवक ने गुरुवार सुबह निवाड़ी गंगनहर में छलांग लगा दी। घरेलू कलह से परेशान होकर युवक ने यह कदम उठाया। पुलिस और गोताखोरों की टीम ने नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया लेकिन युवक का पता नहीं चला। पीड़ित शख्स इंस्टाग्राम पर रील बनाता था। एनडीआरएफ की टीम शुक्रवार को सर्च ऑपरेशन चलाएगी। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

**मोदीनगर।** निवाड़ी गंगनहर में एक युवक बृहस्पतिवार सुबह कूद गया। घरेलू कलह में क्षुब्ध आकर युवक ने यह कदम उठाया। आसपास के लोगों की सूचना पर निवाड़ी पुलिस व गौताखोरों की टीम ने नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन युवक नहीं मिला। निवाड़ी पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम को पत्र लिखा है। उम्मीद है कि आज शुक्रवार को एनडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चलाएगी। निवाड़ी थाना क्षेत्र के गांव भनैड़ा के राशिद (28) कामगार थे। घर में पत्नी व तीन बच्चों के साथ रहते थे। बताया जा रहा है कि घर में पत्नी से कलह चल रही थी। जिसके चलते राशिद तनाव में चल रहे थे। इंस्टाग्राम पर रील भी बनाता था। बृहस्पतिवार सुबह करीब दस बजे वे अपने मोपेड से निवाड़ी पुल पर पहुंचे। पुल पर मोपेड़ खड़ी की और गंगनहर में छलांग लगा दी।

**पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों को नहर में उतारा**

आसपास के लोगों ने यह देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय गोतोखोरों को नहर में उतारा। शाम तक सर्च आपरेशन चलाया लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने मोपेड की मदद से राशिद की पहचान कर स्वजन को सूचना दी। कुछ ही देर में बाद से गांव से काफी संख्या से लोग मौके पर पहुंच गए। घटना के बाद से राशिद के स्वजन को रोरोकर बुरा हाल है। खबर लिखे जाने तक राशिद का सुराग नहीं लगा है।

**युवक को तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी**

एसीपी मोदीनगर ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि गंगनहर में सर्च ऑपरेशन चलाकर राशिद को तलाशने की कोशिश चल रही है। शुरूआती जांच में घरेलू कलह के चलते यह कदम उठाने की बात सामने आ रही है।

**नंदग्राम में एक शख्स का शव फंदे से लटका मिला**

वहीं में एक व्यक्ति का शव बुधवार शाम फंदे पर लटका हुआ मिला। शव के दोनों हाथ-पैर कुत्तों ने काटे हुए थे। सूचना पर पहुची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। फांसी पर लटके शव के दोनों पैर खा गए कुत्ते नंदग्राम में डबल टंकी मोहल्ला के मकान से बुधवार शाम दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने मकान का गेट खोलकर देखा तो मकान मालिक हंसराज (55) का शव फांसी पर लटका था।

## नोएडा एयरपोर्ट के पास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की योजना पर संकट के बादल, ये है बड़ा कारण

नोएडा एयरपोर्ट के पास बनने वाले मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की योजना खटाई में पड़ सकती है। यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में धड़ल्ले से आवासीय भूखंडों की रजिस्ट्री हो रही है। प्राधिकरण ने अलीगढ़ जिला प्रशासन को आवासीय श्रेणी में होने वाली रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए पत्र लिखा है। इस प्रोजेक्ट की लागत 640 करोड़ रुपये है।

**ग्रेटर नोएडा।** टप्पल में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क योजना खटाई में पड़ सकती है। यमुना प्राधिकरण (यीडा) के अधिसूचित क्षेत्र में धड़ल्ले से आवासीय भूखंड की रजिस्ट्री हो रही हैं। प्राधिकरण ने अलीगढ़ जिला प्रशासन को आवासीय श्रेणी में होने वाली रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए पत्र लिखा है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida Airport) के बेहद नजदीक होने के कारण यमुना प्राधिकरण ने टप्पल में मल्टी माडल लाजिस्टिक पार्क की योजना तैयार की है। पहले चरण में दो सौ एकड़ में इसके विकासकर्ता चयन के लिए जल्द ही निविदा जारी होने जा रही है। इसमें 12 वेयरहाउस, छह गोदाम बनेंगे।

यह परियोजना 640 करोड़ की है। लेकिन आसपास के अधिसूचित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कालोनी बस रही हैं। अतिक्रमण को देखते हुए प्राधिकरण ने टप्पल में अधिसूचित शेष 1720 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव भी अलीगढ़ जिला प्रशासन को भेज दिया है। लेकिन अधिसूचित क्षेत्र में हो रही रजिस्ट्री ने प्राधिकरण की नींद उड़ा दी है।

दरअसल क्षेत्र में छोटे-छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री की जा रही है। यह रजिस्ट्री आवासीय श्रेणी में की जा रही है। इससे इस क्षेत्र में आवासीय भवन बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में प्राधिकरण को काफी मुश्किल होगी। आवासीय श्रेणी में रजिस्ट्री होने से भूखंड मालिकों को वहां से हटाना मुश्किल हो जाएगा।

मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क योजना (Multi Modal Logistic Park Yojana) खटाई में पड़ जाएगी। प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र सिंह का कहना है कि अधिसूचित क्षेत्र में आवासीय भूखंड श्रेणी में रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए अलीगढ़ जिला प्रशासन से आग्रह किया गया है।

> पीड़िता ने बताया कि मेरे बेटे की उम्र लगभग 14 वर्ष है। तहरीर के आधार पर पुलिस मुकदमा पंजीकत कर किशोर की तलाश कर रही है।

# सफलता सार्वजनिक उत्सव तो असफलता व्यक्तिगत विप्पति। नतीजों को मिलते पुरस्कार, कोशिशें रहती गुमनाम।

परिणामों पर ज़ोर देने से क्रमिक शिक्षा और सुधार का महत्त्व कम हो जाता है, जिससे सफलता अस्थिर हो जाती है। ऋषभ पंत जैसे क्रिकेटर, जिनकी शुरुआत में असंगतता के लिए आलोचना की गई थी, ने समय के साथ लगातार सुधार करके सम्मान प्राप्त किया। परिणाम-उन्मुख मानसिकता शॉर्टकट या अनैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देती है, जिससे निष्पक्षता और खेल भावना ख़त्म हो जाती है। ऑस्ट्रेलियाई बॉल-टैम्परिंग घटना जैसे घोटाले ईमानदारी पर जीत को प्राथमिकता देने की लागत को दर्शाते हैं। समाज विजेताओं का महिमामंडन करता है लेकिन प्रतिभागियों के प्रयासों की उपेक्षा करता है, जिससे खेलों की समावेशिता और एकीकृत भावना कमजोर होती है। कम प्रसिद्ध ओलंपियन जो अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं लेकिन पदक जीतने में विफल रहते हैं, उन्हें स्वर्ण पदक विजेताओं की तुलना में कम मान्यता मिलती है। प्रयास को स्वीकार करने से सहानुभूति, सहयोग और एकता जैसे मूल्य पैदा होते हैं, जो एक परिपक्व और नैतिक समाज में योगदान करते हैं। 2019 क्रिकेट विश्व कप सेमीफाइनल में भारत के प्रयासों का जश्न मनाने वाले प्रशंसकों ने परिणामों से ज़्यादा प्रयास की सराहना करने की ओर एक बदलाव दिखाया।

-डॉ सत्यवान सौरभ

सफलता सार्वजनिक उत्सव होती है, जबकि असफलता व्यक्तिगत विपत्ति होती है।

सफलता में लोग साथ होते हैं, जबकि असफलता में लोग छोड़ देते हैं। हालांकि, असफलता से सीखने और बढ़ने का मौका मिलता है। सफलता सार्वजनिक उत्सव है जबकि असफलता व्यक्तिगत शोक एकदम सत्य लिखा है। दो ऐसे शब्द जो हर व्यक्ति के जीवन में बहुत मायने रखते हैं। पहला शब्द सफलता जिसको हर कोई प्राप्त करना चाहता है जबकि दूसरा शब्द असफलता जिससे हर व्यक्ति दूर रहना चाहता है। सफलता जब प्राप्त होती है तो घर-परिवार सब खुश होता है लेकिन असफलता का सामना आपको अकेले ही करना पड़ता है। अगर आप सफल हो गए तो समाज में आपकी इज़्ज़त होगी, लोगों का आपके साथ व्यवहार परिवर्तित हो जायेगा लेकिन असफल रहने पर आपको बेरोजगार, ठलुआ जैसी संज्ञा मिलेंगी। मायने ये भी रखता है कि आपने सफलता प्राप्त करने के लिए कितना प्रयत्न किया? यदि आपने पूरे समर्पण के भाव से मेहनत की है फिर भी आप अपने मनपसंद क्षेत्र में सफल नहीं हुए तो ये मान लीजिए कि आपने अपने सपने को पूरा करने के लिए जो ज्ञानार्जन किया है वह आपके भावी जीवन में बहुत काम आने वाला है। वही ज्ञान किसी अन्य क्षेत्र में आपका भविष्य निर्माण करने में सहायक हो सकता है।

परिणाम-संचालित समाज में, प्रयास अक्सर परिणामों के पीछे चला जाता है, परिणाम-संचालित समाज में, परिणामों पर प्रयास को प्राथमिकता देना योग्यता के सिद्धांत को चुनौती देता है। खेलों में, प्रयास दृढ़ता, अनुशासन और निष्पक्षता को दर्शाता है, जो प्रदर्शन पर प्रक्रिया पर ज़ोर देता है। यह दृष्टिकोण मानसिक लचीलापन और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है जबकि डोपिंग और मैच फिक्सिंग जैसी अनैतिक प्रथाओं के दबाव को कम करता है। नैतिक मूल्यांकन को मापने योग्य परिणामों के साथ प्रयास के आंतरिक मूल्य को संतुलित करना चाहिए। मापनीय परिणामों के प्रति जुनून, समाज मात्रात्मक सफलता को प्राथमिकता देता है, अक्सर प्रयास के आंतरिक मूल्य और यात्रा में दृढ़ता को अनदेखा करता है। माता-पिता बच्चे के परीक्षा अंकों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन शायद ही कभी अध्ययन या अवधारणाओं को समझने में बिताए गए समय को स्वीकार करते हैं। परिणामों पर लगातार ध्यान केंद्रित करने से अनावश्यक दबाव बनता है, जिससे तनाव होता है और सुधार या सीखने के लिए आंतरिक प्रेरणा कम हो जाती है।

रिकॉर्ड तोड़ने के दबाव का सामना करने वाले एथलीट कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय डोपिंग का सहारा ले सकते हैं। परिणामों पर ज़ोर देने से क्रमिक शिक्षा और सुधार का महत्त्व कम हो जाता है, जिससे सफलता अस्थिर हो जाती है। ऋषभ पंत जैसे क्रिकेटर, जिनकी शुरुआत में असंगतता के लिए आलोचना की गई थी, ने समय के साथ लगातार सुधार करके सम्मान प्राप्त किया। परिणाम-उन्मुख मानसिकता शॉर्टकट या अनैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देती है, जिससे निष्पक्षता और खेल भावना ख़त्म हो जाती है। ऑस्ट्रेलियाई बॉल-टैम्परिंग घटना जैसे घोटाले ईमानदारी पर जीत को

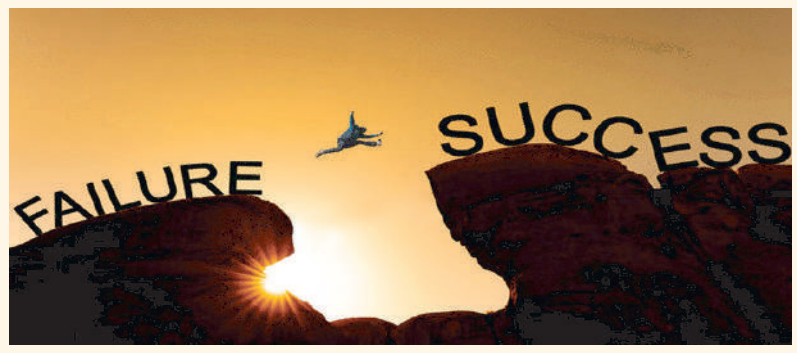


प्राथमिकता देने की लागत को दर्शाते हैं। समाज विजेताओं का महिमामंडन करता है लेकिन प्रतिभागियों के प्रयासों की उपेक्षा करता है, जिससे खेलों की समावेशिता और एकीकृत भावना कमजोर होती है। कम प्रसिद्ध ओलंपियन जो अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं लेकिन पदक जीतने में विफल रहते हैं, उन्हें स्वर्ण पदक विजेताओं की तुलना में कम मान्यता मिलती है।

निष्पक्षता और समावेशिता को बढ़ावा देना, प्रयास को महत्त्व देना सुनिश्चित करता है कि सभी प्रतिभागियों को मान्यता प्राप्त हो, एक समावेशी और सहायक वातावरण को बढ़ावा मिले। पैरालिंपिक खेल दृढ़ता और प्रयास को उजागर करते हैं, पदकों पर भागीदारी पर ज़ोर देते हैं। प्रयास को प्राथमिकता देने से व्यक्तियों को दृढ़ता, विनम्रता और भावनात्मक शक्ति का निर्माण करने में मदद मिलती है, जो व्यक्तिगत विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है। नीरज चोपड़ा की विनम्रता और प्रतियोगियों के प्रति सम्मान सिर्फ़ उनके भाला फेंक रिकॉर्ड से कहीं ज़्यादा मनाया जाता है। प्रयास पर ध्यान केंद्रित करने से कौशल वृद्धि और निरंतरता को बढ़ावा मिलता है, जिससे खेलों में स्थायी उपलब्धियाँ मिलती हैं। विराट कोहली की अनुशासित प्रशिक्षण दिनचर्या स्थायी सफलता प्राप्त करने में प्रयास के महत्त्व को दर्शाती है। परिणामों से ज़्यादा प्रयास को महत्त्व देने से नैतिक व्यवहार और नियमों के प्रति सम्मान को बढ़ावा मिलता है, जिससे खेलों में निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।

उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर का स्लेजिंग में शामिल होने से इनकार करना क्रिकेट में अल्पकालिक लाभ की तुलना में नैतिकता को उजागर करता है। प्रयास को स्वीकार करने से सहानुभूति, सहयोग और एकता जैसे मूल्य पैदा होते हैं, जो एक परिपक्व और नैतिक समाज में योगदान करते हैं। 2019 क्रिकेट विश्व कप सेमीफाइनल में भारत के प्रयासों का जश्न मनाने वाले प्रशंसकों ने परिणामों से ज़्यादा प्रयास की सराहना करने की ओर एक बदलाव दिखाया। परिणामों से ज़्यादा प्रयास को महत्त्व देने से नैतिक सिद्धांतों को बढ़ावा मिलता है, खेलों में निष्पक्षता और समावेशिता की संस्कृति का पोषण होता है। यह दीर्घकालिक चरित्र निर्माण को बढ़ावा देता है और अनैतिक शॉर्टकट को रोकता है। हालांकि, एक सूक्ष्म दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण है, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रयास कौशल विकास और प्रदर्शन लक्ष्यों के साथ संरेखित हों, ताकि प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बनाए रखा जा सके और साथ ही खेल कौशल और अखंडता को बढ़ावा दिया जा सके।

कभी कभी हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण क़दम उठाते हैं परीक्षा से इतर। अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आगे बढ़ते हैं, पूरी जी जान से मेहनत करते हैं ताकि कुछ अच्छा हो लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि आप सफल हो ही जाएँ। सफलता और असफलता दोनों के ही मौके समान रहते हैं। आप सफल हुए तो आपके अब तक के संघर्ष पर पूर्ण विराम लग जाएगा लेकिन दूसरी स्थिति बहुत विकट होती है जब आप अपनी मेहनत को डूबता हुआ देखते हैं। युवाओं के लिए यह स्थिति और भी ज़्यादा खराब होती है क्योंकि वह ऐसी स्थिति का सामना जीवन में पहली बार कर रहे होते हैं। ऐसे समय में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना ही सर्वोत्तम उपाय है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही हिम्मती और धैर्यवान लोगों के लिए ही लिखा गया है-कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंत में केवल इतना कहूंगा अपने कार्य के प्रति सदैव ईमानदार, निष्ठावान, समर्पित और वफादार रहो चाहे नौकरी हो या व्यापार।

# मारुति सुजुकी ई विटारा की रेंज कंफर्म, ऑटो एक्स्पो 2025 में होगी पेश

परिवहन विशेष न्यूज

Maruti Suzuki e Vitara Range Confirmed Auto Expo 2025 में पेश होने से पहले मारुती सुजुकी ई-विटारा की रेंज की डिटेल्स सामने आ गई है। इसमें लगी हुई बैटरी फुल चार्ज होने के बाद 500 किमी से ज्यादा तक की रेंज देने में सक्षम रहेगी। e Vitara में 49 kWh पैक और 61kWh दो बैटरी बैक मिल सकते हैं। मारुति की यह पहली इलेक्ट्रिक कार है।

**नई दिल्ली।** ऑटो एक्सपो 2025 में मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV e Vitara को पेश करने वाली है। कंपनी ने टोयोटा के साथ मिलकर इसके हार्टेक्ट-ई प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है। ई-विटारा में कई बैचरी पैक ऑप्शन के साथ ही ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम भी मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि Maruti Suzuki e Vitara में कितनी रेंज मिलने वाली है और यह किन फीचर्स से लैस रहने वाली है।

**एक्सटीरियर**

हाल ही में इसका एक टीजर जारी किया गया था, जिसमें इसकी बाहर की डिजाइन देखने के लिए मिली थी। इसमें ट्राई-स्लैश एलईडी डेटाइम रनिंग लाइट और बीच में मारुति सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिला था। इसके साथ ही स्कल्प्टेड बोनट और एक बोल्ड बम्पर भी दिखाई दिया था।

इसके पीछे और साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें 18-इंच के अलॉय व्हील, सी-पिलर-माउंटेड डोर हैंडल, व्हील आर्च क्लैडिंग, रूफ स्पॉइलर, शार्क-फिन एंटीना, मजबूत रियर बंपर और लाइटबार-स्टाइल टेल लैंप देखने के लिए मिल सकते हैं।

**इंटीरियर**

Maruti Suzuki e Vitara के इंटीरियर की बात करें तो इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम इंटीग्रेटेड स्क्रीन देखने के लिए मिल सकती है। इसका डैशबोर्ड को डुअल-टोन इंटीरियर के साथ पेश किया जा सकता है। इसमें दो-स्पोक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील और अपडेटेड एसी वेंट भी दिए जा सकते हैं, जो इसकी फंक्शनैलिटी और डिजाइन को और भी बढ़ा देगा।

**फीचर्स**

Maruti Suzuki e Vitara में पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। वहीं, पैसेंजर की सेफ्टी के लिए छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) मिल सकता है।

**बैटरी पैक और रेंज**

मारुति सुजुकी ई-विटारा को टोयोटा के सहयोग से डेवलप किया गया है और इसे स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसमें दो बैटरी पैक देखने के लिए मिलेगा, जो 49 kWh पैक और 61 kWh है। इसके मोटर को दो-पहिया या चार-पहिया ड्राइव के साथ जोड़ा जा सकता है। इसकी बैटरी की रेंज को लेकर पुष्टि की गई है कि Maruti Suzuki e Vitara फुल चार्ज होने बाद 500 किमी से ज्यादा की रेंज मिलेगी।

मारुति सुजुकी की तरफ से कहना है कि बैटरी पैक का वजन 600 से 700 किलोग्राम के बीच है। बैटरी के हल्के होने की वजह से इसकी कैपेसिटी और लंबी ड्राइविंग रेंज मिलने में अहम भूमिका रहेगी।

# ऑटो एक्स्पो 2025 में टाटा शोकेस करेगी ये कारें, लिस्ट में ICE-EV से लेकर कॉनेप्ट कार शामिल

परिवहन विशेष न्यूज

Tata Cars Auto Expo 2025 ऑटो एक्सपो 2025 में Tata Motors अपनी ICE और इलेक्ट्रिक कार के साथ ही कॉन्सेप्ट कार को भी पेश कर सकती है। इसके साथ ही इनके पवेलियन में Altroz Racer Dark Edition Curve Dark Edition Curve EV Dark Edition भी देखने के लिए मिल सकता है। वहीं टियागो और टियागो ईवी भी देखने के लिए मिल सकती है।

**नई दिल्ली।** ऑटो एक्सपो 2025 का आयोजन 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच होने वाला है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक कारों को पेश करने की तैयारी कर रही है। इनके इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में कई नए वाहन, अन्य ग्रीन फ्यूल तकनीक और अपने ICE SUV के कुछ लिमिटेड वेरिएंट पेश करेगी। आइए जानते हैं कि Tata Motors Auto Expo 2025 में कौन-सी इलेक्ट्रिक कारें दिखाने वाले है।

**Tata Harrier EV**

टाटा मोटर्स की हैरियर EV को ऑटो एक्सपो 2025 में पेश किया जाएगा। यह टाटा की मुख्य इलेक्ट्रिक SUV है, जिसे जल्द ही भारत में लॉन्च किया जा सकता है। ऑटो एक्सपो 2025 में पेश होने जा रही है, जो पिछले लुक से हटकर होने वाली है, जो प्रोडक्शन-स्पेक के करीब होगी।

डिजाइन के मामले में, हैरियर EV अपने ICE वर्जन के समान ही रहने वाली है। इसमें क्लोज ग्रिल जैसे कुछ EV-स्पेशल एलिमेंट देखने के लिए मिलेंगे। इसमें नया एयरोडायनामिक व्हील डिजाइन देखने के लिए मिल सकते हैं।

Harrier EV में 60 kWh से 80 kWh के बैटरी पैक देखने के लिए मिल सकते हैं, जो फुल चार्ज के बाद 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकते हैं। इसमें रियर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के साथ वैकल्पिक डुअल-मोटर AWD लेआउट भी मिल सकता है।

**Tata Sierra EV**

Harrier EV की तरह ही सिएरा को भी पहले कई मौकों पर कॉन्सेप्ट के रूप में पेश किया जा चुका है। अब यह कॉन्सेप्ट रूप से आगे बढ़ चुकी है, जो प्रोडक्शन-स्पेक के करीब पहुंच गई है। ऑटो एक्सपो 2025 में इसके प्रोडक्शन के करीब वर्जन को पेश किया जा सकता है।

नई सिएरा हैरियर ईवी और सफारी ईवी जैसे ही अंडरपिनिंग से लैस हो सकती है। इसके ICE वर्जन को भी लाया जाएगा, जिसे आने वाले वर्षों में लॉन्च किया जा सकता है।

**Tata Avinya Concept**

टाटा अविन्या कॉन्सेप्ट को साल 2022 में पहली बार पेश किया गया था। इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों में ही फ्यूचरिस्टिक झलक देखने के लिए मिल सकती है। इस बार के ऑटो एक्सपो में भी इसके कॉन्सेप्ट मॉडल ही देखने के लिए मिल सकता है या फिर कंपनी अविन्या कॉन्सेप्ट से बनी किसी गाड़ी को शोकेस कर सकती है।

**ये गाड़ियां भी कर सकती है शोकेस**

टाटा मोटर्स ऊपर बताई गई गाड़ियों के अलावा अपनी मौजूदा एसयूवी और हैचबैक के कुछ स्पेशल वेरिएंट को भी शोकेस कर सकती है। ऑटो एक्सपो 2025 में Altroz Racer Dark Edition, Curve Dark Edition, Curve EV Dark Edition को पेश किया जा सकता है। इतना ही नहीं, 2025 टियागो और टियागो ईवी के साथ-साथ मौजूदा डुअल-सिलेंडर आई-सीएनजी कार को भी पेश कर सकती है। इसके अलावा टाटा अपने पवेलियन में फ्लेक्स-फ्यूल वाहन को भी दिखा सकता है।

# हीरो स्पलेंडर का आएगा इलेक्ट्रिक वर्जन, भारत में 2027 तक हो सकती है लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

टू-व्हीलर निर्माता कंपनी Hero अपनी सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिल Splendor का इलेक्ट्रिक वर्जन लाने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Hero Splendor Electric को साल 2027 तक लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही हीरो दो प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक भी लाने की तैयारी कर रही है जो 150cc और 250cc ICE मोटरसाइकिल के बराबर होंगी।

**नई दिल्ली।** इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में अब कई मोटरसाइकिल और स्कूटर आ चुके हैं। कई कंपनियां इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए अपनी नई गाड़ियां भी लेकर आने वाली है। वहीं, अब हीरो की सबसे पॉपुलर Splendor बाइक की इलेक्ट्रिक वर्जन आने वाली है। कंपनी ने इसे जल्द भारतीय बाजार में लाने की तैयारी में लगी हुई है। इसे साल 2027 तक भारत में लॉन्च किया जा सकता है।

**हीरो स्प्लेंडर इलेक्ट्रिक पर कर रही काम:** मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हीरो मोटोकॉर्प इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। हाल ही में कंपनी ने विडा इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेश किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी 6 से ज्यादा नए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर काम कर रही है, जिन्हें अलगे दो से तीन वर्षों में लॉन्च किया जा सकता है। इन इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर में से एक स्प्लेंडर इलेक्ट्रिक भी रहने वाली है। स्प्लेंडर इलेक्ट्रिक को हीरो की सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना बताया गया है। 2027 में इसे भारत में लॉन्च किया जा सकता है। हाल में इसे जयपुर में हीरो के प्लांट में डेवलप किया जा रहा है।

**इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक पर भी कर रही काम:** Splendor Electric के अलावा कंपनी 2026 में Lynx इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक को लॉन्च करने पर भी काम कर रही है। इस बाइक का उत्पादन हर साल 10,000 यूनिट हो सकता है। Lynx के साथ ही बच्चों के लिए एक्रो लर्नर इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक को भी लॉन्च किया जा सकता है। इसे हाल ही में भारत में पेटेंट कराया गया है।

**प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक पर भी हो रहा काम**

रसलेन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हीरो दो प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को भी लेकर आने वाली है। ये इसेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 150cc और 250cc ICE के बराबर होने वाली है। यह स्टाइलिश होने के साथ ही परफॉर्मेंस वाली भी होंगी।

# भारत मोबिलिटी 2025 आज से होगा शुरू, ऑटो एक्स्पो में पेश होंगी कई कारें, टिकट, टाइमिंग, वेन्यू की पढ़ें जानकारी

परिवहन विशेष न्यूज

Bharat Mobility 2025 17 जनवरी से 22 जनवरी 2025 के बीच भारत मोबिलिटी का आयोजन किया जा रहा है। जिसके तहत Auto Expo 2025 में कई बेहतरीन बाइक स और कारों को पेश और लॉन्च किया जाएगा। अगर आप भी कारों को देखने की तैयारी कर रहे हैं तो कार्यक्रम की Ticket Timing Venue की पूरी जानकारी हम इस खबर में आपको दे रहे हैं।

**नई दिल्ली।** नई तकनीक, फीचर्स और डिजाइन वाली कारों के साथ भविष्य के वाहनों को शोकेस करने के लिए 17 जनवरी 2025 से 22 जनवरी 2025 के बीच Bharat Mobility 2025 के तहत Auto Expo 2025 का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की Ticket Price, Venue और Timing की पूरी जानकारी (Auto Expo Ticket and Timing Information) हम इस खबर में आपको दे रहे हैं।

**दिल्ली में होगा Bharat Mobility 2025 का आयोजन**

भारत सरकार की ओर से भारत मोबिलिटी के दूसरे संस्करण में आयोजित किए जाने वाले Auto Expo 2025 को दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में किया जाएगा। यहीं पर देश और दुनिया की प्रमुख वाहन निर्माताओं की ओर से नई कारों, स्कूटर और बाइक्स को पेश और लॉन्च किया जाएगा।

**कैसे मिलेगी एंट्री**

Auto Expo 2025 को देखने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप Bharat Mobility 2025 की वेबसाइट पर जाकर Visitor Registration के फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। जिसके बाद आप ऑटो एक्सपो 2025 में बिना परेशानी एंट्री ले सकते हैं।

**कितने की होगी टिकट**

भारत मोबिलिटी 2025 के तहत ही ऑटो एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति इसे देखने के लिए जा सकता है। इसकी टिकट (Auto Expo 2025 tickets) के लिए किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह पूरी तरह से फ्री रहेगी।

**आम जनता के लिए कब से खुलेगी एंट्री**

ऑटो एक्सपो 2025 का आयोजन वैसे तो 17 जनवरी 2025 से हो जाएगा। 18 जनवरी को सिर्फ खास तौर पर इनवाइट किए गए व्यक्तियों के लिए रिजर्व रखा गया है। आम जनता के लिए इसे 19 जनवरी से खोला (Auto Expo 2025 public entry) जाएगा। 19 से 22 जनवरी 2025 के बीच सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच (Auto Expo 2025 timing) एक्सपो को विजिट किया जा सकता है।

**कौन सी कंपनियां ले रहीं हिस्सा**

Auto Expo 2025 में कई प्रमुख वाहन निर्माताओं की ओर से हिस्सा लिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में Maruti Suzuki, Hyundai, Tata Motors, Kia, Mahindra, BMW, Mercedes Benz, JSW MG, Skoda, Volkswagen, Porsche, BYD, Vinfast के साथ ही Bajaj Auto, Hero Motocorp, Honda Motorcycle and Scooter India (HMSI), Yamaha सहित करीब 34 से ज्यादा वाहन निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। जिनमें से कुछ विदेशी निर्माता भी होंगे जो पहली बार इसका हिस्सा बन रहे हैं।

# पीएम मोदी करेंगे ऑटो 2025 का उद्घाटन, यहां जानिए टाइमिंग से लेकर टिकट तक की जानकारी

परिवहन विशेष न्यूज

ऑटो एक्स्पो 2025 का आयोजन PM Modi करेंगे। इस बार ऑटो एक्सपो का आयोजन 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी 2025 तक आयोजित होने वाला है। इसे नई दिल्ली के भारत मंडपम द्वारका में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर स्थल और ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इसके टिकट पूरी तरह से निशुल्क है। इसके लिए आपको भारत मोबिलिटी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

**नई दिल्ली।** भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच आयोजित होने जा रहा है। इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह भारत का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो है, जिसमें 100 से ज्यादा ऑटोमेकर हिस्सा लेने वाले हैं। आइए जानते हैं ऑटो एक्सपो 2025 कहां पर होने वाला है और इसकी टिकट के लिए कितने पैसे लगेंगे और इसकी टाइमिंग कबसे रहने वाली है।

**ऑटो एक्सपो 2025 की तारीख**

ऑटो एक्सपो 2025 का आयोजन 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी 2025 के बीच होने वाला है। इसका पहला दिन मीडिया कर्मियों के लिए रिजर्व रखा गया है और दूसरा दिन स्पेशल इनविटेशन के लिए निर्धारित किया गया है। इसे आम लोगों को एंट्री ऑटो एक्सपो के तीसरे दिन यानी 19 जनवरी से 22 जनवरी तक मिलेगी।

**ऑटो एक्सपो 2025 का स्थान**

ऑटो एक्सपो 2025 का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। यह भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के लिए घोषित तीन प्रमुख स्थानों में से एक हैं। ऑटो एक्सपो को भारत मंडपम के हॉल 1 से हॉल 14 ग्राउंड फ्लोर तक आयोजित किया जाएगा।

अगर आप ऑटो एक्सपो कंपोनेंट्स शो में हिस्सा लेने के लिए आपको द्वारका में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर स्थल पर जाना पड़ेगा। वहीं, ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट निर्दिष्ट तिथियों के दौरान भारत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है।

**ऑटो एक्सपो 2025 की टिकट और मूल्य**

ऑटो एक्सपो 2025 में शामिल होने के लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इसमें जाने के लिए आपको Bharat Mobility Global Expo की वेबसाइट पर जाकर खुद को पंजीकृत करना होगा। यहां पर आपको अपने पसंदीदा जगह और दूसरी जानकारी के साथ पंजीकरण के तहत फॉर्म भरना होगा।

**इन शो का होगा आयोजन**

ऑटो एक्सपो 2025 में इंडिया इंटरनेशनल टायर शो, भारत बैटरी शो, स्टील पवेलियन, मोबिलिटी टेक पवेलियन और इंडिया साइकिल शो का आयोजन किया जाएगा। इन सभी शो का आयोजन करने के पीछे का कारण मोबिलिटी से जुड़े सभी सेक्टरों को एक साथ एक प्लेटफार्म पर लाना है।

# 18 जनवरी को भारत में एंट्री करेगी विनफास्ट, इंटरनेशनल पोर्टफोलियो से लाएगी कई इलेक्ट्रिक कारें और बाइक

वियतनाम की Electric Car निर्माता Vinfast भी Auto Expo 2025 में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही है। कंपनी की ओर से 18 January 2025 से भारत में अपने सफर की शुरुआत की जाएगी। इस दौरान कंपनी की ओर से किन Cars And SUVs को शोकेस किया जाएगा। इनमें से कौन सी कारों को आने वाले महीनों में लॉन्च किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

**नई दिल्ली।** वियतनाम की वाहन निर्माता Vinfast की ओर से भारतीय बाजार में औपचारिक तौर पर एंट्री लेने की तैयारी की जा रही है। कंपनी की ओर से Auto Expo 2025 के दौरान कौन सी Cars and Bikes को शोकेस किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

**Auto Expo 2025 से शुरू करेगी सफर**

Vinfast भारत में अपने सफर की शुरुआत Auto Expo 2025 से करेगी। कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है कि वह 18 January 2025 को Bharat Mobility Global Expo 2025 में अपनी कई कारों और बाइक्स को शोकेस करेगी, जिनमें से कुछ वाहनों को भारत में अगले कुछ महीनों के दौरान लॉन्च भी किया जाएगा।

**शोकेस होंगी ये Electric Cars**

जानकारी के मुताबिक Vinfast की ओर से भारत में कई कारों और बाइक्स को लाया जाएगा। जिनमें VF3, VF5, VF6, VF7, VF8, VF9, VF Wild और VF e34 इलेक्ट्रिक कारें शामिल होंगी। इनके साथ ही कंपनी की ओर से VF Dragon Fly E Bike को भी शोकेस किया जाएगा।

**भारत आएंगी ये कारें**

Auto Expo 2025 में शोकेस की जाने वाली कारों में से कुछ को Vinfast की ओर से भारत में लॉन्च किया जाएगा। इन कारों को साल 2025 और 2026 के दौरान भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। जिनमें पांच सीटों वाली VF7 और सात सीटों वाली VF9 शामिल हैं।

**कैसे होंगे फीचर्स**

भारत में सबसे पहले जिन Electric SUVs को लॉन्च किया जाएगा उनमें VF7 और VF9 होंगी। इन एसयूवी में कंपनी कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। दोनों एसयूवी में एलईडी लाइट्स, एलईडी डीआरएल के अलावा एलईडी टेल लाइट्स, फ्लश डोर हैंडल, 20 से 21 इंच के बीच अलॉय व्हील्स, 360 डिग्री कैमरा, ड्यूल टोन एक्सटीरियर के साथ इंटीरियर, एंबिएंट लाइट्स, पैनोरमिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12 से 15 इंच के बीच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटिड सीट्स, स्मार्ट की, ड्राइविंग के लिए कई मोड्स, प्रीमियम इंटीरियर के साथ ही कई बेहतरीन फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स को दिया जा सकता है।

# विकास के सपने और हकीकत

विजय गर्ग

भारतवासियों ने बड़ी उम्मीद के साथ इस नए वर्ष का स्वागत किया है। सत्ता ने उन्हें बताया है कि दुनिया में आज भारत का सानी नहीं अंतरिक्ष से लेकर अर्थव्यवस्था तक इसका डंका बज रहा है। कहा जा रहा है कि भारत अपने अतीत को भविष्य में बदल देगा। यानी वह विश्वगुरु था और 'अब फिर बन फिर बन जाएगा। वैसे भी अब 'जय जवान जय किसान' से 'जय अनुसंधान' हो गया है। देश तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का महत्त्व इतना बढ़ गया है कि उसकी। उपेक्षा नहीं की जा जा सकती। मगर अपना प्रशस्ति गान करने के इस दंभ में कुछ चुनौतियां भी देश की अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी हो गई हैं। ये पहले से शुरू हो गई थीं और सिवाय मंचीय भाषणों और दावों के, इन समस्याओं को हल करने का कभी गंभीर प्रयास नहीं किया गया। भूख मिटाने की गारंटी तो दे दी, लेकिन देश के बेकार हाथों को काम देने की गारंटी नहीं दी। देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई, लेकिन उसके लिए कच्चे माल और ऊर्जा ऊर्जा स्रोतों का सृजन भारत में। आजादी का अमृत महोत्सव' मनाया गया। महोत्सव के बाद हुई कि अब त्वरित गति से पूंजी निर्माण होगा। इसके साथ ही देश में बुनियादी उद्योगों की ऐसी नींव डाली जाएगी कि फुटकर उद्योगों को अपना रास्ता पकड़ने में कठिनाई नहीं होगी। दुनिया में भारत की आबादी सभी देशों से अधिक हो गई है। इस आबादी को काम देने के लिए सहकारी आंदोलन 1 को नया जीवन देने की घोषणा संसद में बार- बार होती रही। मगर अभी तक यह सहकारी आंदोलन अपने पुराने भ्रष्टाचारों के आतंक से बाहर नहीं आ सका है। बार-बार एक लाख जवानों को राजनीति में लाने की बात हुई, लेकिन नजर आया कि देश र के नाम पर परिवारवाद ही प्रोत्साहित हो रहा है।

देश नौजवानों की रगों में नए में नहीं हुआ।

आज वर्ष की एक सार्थक के शुरुआत करने की बात कहनी हो, हमें देश के बुनियादी उद्योगों का सबल विकास, नींव के रूप में बनाने पर चर्चा करनी' चाहिए, लेकिन पहला सवाल यही है कि बीते नवंबर में देश के आठ बुनियादी उद्योगों में उत्पादन धीमा कैसे हो गया। आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि यह 4.3 फीसद रहा। एक साल पहले यह 7.9 फीसद था ऐसा क्यों हुआ ? क्योंकि हमारा सपना तो दुनिया की पांचवीं आर्थिक महाशक्ति से आगे बढ़ कर तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनना है। मगर नवंबर 2024 कहता बीत गया कि कच्चे तेल गैस के उत्पादन में कमी आई है। कोयला, रिफाइनरी

और प्राकृतिक उत्पाद, उर्वरक, इस्पात और बिजली के उत्पादन में वृद्धि के बजाय कमी नजर आने लगी है। सबसे अधिक कमी कोयला उत्पादन में आई है, कोई 7.5 फीसद जबकि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा की बहुत बातें होती हैं। इसके उपयोग के लिए तैयार होने वालों के लिए कुछ प्रोत्साहन भी घोषित किए गए हैं, लेकिन इस देश में लोग आज भी कोयले को ही ताप और ऊर्जा का बड़ा साधन मानते हैं।

जब इन मूल उद्योगों के उत्पादन की ओर पिछले वर्ष के आंकड़ों को जांचते हैं, तो पाते हैं कि तुलनात्मक ढंग से आज की तुलना में तब इन सभी बुनियादी उद्योगों में विकास की गति अधिक थी। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि इस वर्ष अप्रैल-नवंबर के दौरान बुनियादी ढांचे की वृद्धि दर 4.2 फीसद रही। जबकि पिछले वित्तवर्ष में यह 8.7 फीसद थी। बुनियादी ढांचे के विकास को इतनी बड़ी ठोकर क्यों लगी ? इसका कारण है कि निवेशक और उद्योगपति अपने हर निवेश से त्वरित लाभ की आशा करते हैं, लेकिन देश का बुनियादी ढांचा तो केवल भावी उत्पादन का आधार बनता है। देश के विकास का ठोस धरातल बनता है इसलिए तत्काल लाभ न मिलने की वास्तविकता के कारण निजी निवेशक इस ओर पैसा नहीं लगाना चाहते वादे के बावजूद सरकार पूंजी निर्माण और बुनियादी उद्योगों के विकास के लिए अतिरिक्त राशि नहीं निकाल पाती। जहां तक अनुसंधान का संबंध है, हमने 'जय अनुसंधान' न' तो कह दिया, लेकिन दूसरी महाशक्तियों के मुकाब

अनुसंधान के लिए व्यय उनसे तीन-चार गुना कम है। इसके लिए गंभीर प्रयास भी नजर नहीं आते। अंततः इसका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय व्यापार में देश की साख पर पड़ता है।

हम अपने दवा उत्पादन क्षेत्र पर बहुत गर्वित होते रहे हैं। जब कई दावों के बाद दुनिया में दवाओं और अन्य संबंधित वस्तुओं का निर्यात बढ़ा, तो पता चला कि यहां स्तरहीन दवाओं का निर्माण हो रहा है। नकली दवाएं भी खूब बन रहीं। बाद में देश को मिले निर्यात के आदेश निरस्त होने लगे। दवाएं वापस आकर देश के निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनने के सपनों को झुठलाने लगीं। केवल दवाएं ही क्यों, हमने जो माल इस देश से निर्यात किया, वह अधिक लागत वाला माना गया। इसके लिए विदेशों से निर्यात के वो आदेश हमें नहीं मिले, जिसकी हमें । उम्मीद थी। अधिकतर पैसा तेजी से विकसित होते कुछ देशों की ओर चला गया। आप देखिए कि दुबई में भारतीयों ने कितना पैसा लगाया क्योंकि वहां व्यापार की सहजता और सुलभता है। ऐसा तीसरी दुनिया के अन्य कई देशों में भी है।

भारत कार्य व्यापार के दावों को सहज करने के बावजूद नौकरशाही और लालफीताशाही की नाक में नकेल नहीं डाल सका। अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षक बताते हैं कि सुधार के दावे तो बहुत किए गए, लेकिन उत्पादन हर चरण पर इजाजत का ऐसा चक्रव्यूह व्यापारियों को झेलना पड़ता था कि उन्होंने भी उन देशों का रुख करना शुरू कर दिया, जहां नियम कायदों का यह तंत्र जाल नहीं था। तंत्र के हर मोड़ पर भ्रष्ट अधिकारी अपना मुंह खोले बैठे थे। नया युग लाना है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दुविधा यही है कि हमारी मुद्रा डालर के मुकाबले लगातार गिरती जा रही है और हमारे स्वर्ण भंडार का का क्षरण हो रहा है। इस समय डालर मुकाबले रुपया 86 रुपए प्रति डालर से ऊपर चला गया है। इस गिरावट को थामने के लिए हम वैकल्पिक मुद्रा भी प्रयोग नहीं कर सकते, जैसा ब्रिक्स सम्मेलन म्मेलन के दौरान सोचा गया था।

दूसरी ओर, बचत के पारंपरिक तरीके सोने की तेजी को छू नहीं पा रहे। चांदी भी लगातार तेज हो रही है। देश में आर्थिक सुरक्षा के लिए सोने का संग्रह करना पुरानी रिवायत है। सोने के पीछे बौराई जनता उसे इस नए आर्थिक वर्ष में 90 हजार रुपए प्रति तोला तक ले जा सकती है। अभी यह अस्सी हजार पार करने को बेताब है। यह न भूलें कि सोने का अपने देश में उत्पादन बहुत कम है। मुख्यतः सोना भी आयात किया जाता है। अब अगर आर्थिक सुरक्षा की तलाश में देशवासी सोने-चांदी जमा करने के लिए भागते हैं, तो अंदाजा लगाइए कि इन मूल्यवान धातुओं के आयात से हमारी आयात व्यवस्था कैसे गड़बड़ा जाएगी और जिस देश को हम निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की बार-बार घोषणा करते हैं, क्या यह घोषणा मात्र एक सपना ही रहेगी ?

# सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड परीक्षा -2025 में प्रश्न पत्र का हल करने के लिए युक्तियाँ

विजय गर्ग

बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पत्र को ठीक से हल करने से आपको उच्च अंक प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। पेपर प्रेजेंटेशन एक महत्वपूर्ण पहलू है और आपको पेपर को इस तरह से हल करना चाहिए कि न केवल चेकर पर प्रभाव पड़े बल्कि वह आपका पेपर आसानी से पढ़ सके। बोर्ड पेपर का प्रयास करते समय आपको निम्नलिखित कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए: 1. सबसे पहले प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ें सबसे पहली बात तो यह है कि अपना पेपर अच्छे से पढ़ें, उसे अच्छे से समझें। उत्तर लिखते समय आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि क्या पूछा जा रहा है और इसमें कितने अंक हैं। उत्तर तदनुसार-तार्किक एवं व्यापक रूप से लिखना चाहिए। 2. पहले 15 मिनट का प्रभावी ढंग से उपयोग करें आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए शुरुआत में 15 मिनट का अच्छा समय मिलता है - इस समय का उपयोग केवल यही करने के लिए करें, पढ़ें। 15 मिनट में सभी 30 प्रश्न पढ़ें। पढ़ते समय प्रश्नों को आसान, प्रबंधनीय और कठिन श्रेणियों के अनुसार चिह्नित करें। ऐसा प्रश्नों के बारे में समग्र विचार करने और एक मोटी योजना बनाने के लिए किया जाता है। 3. कठिन लोगों के बारे में चिंता मत करो जिस क्षण आपको पता चलता है कि कुछ कठिन प्रश्न हैं; यह स्वाभाविक है कि आप उनके बारे में चिंता करने लगें। इसकी आवश्यकता नहीं है और यह केवल आपके प्रदर्शन को नुकसान पहुंचाएगा। तथ्य यह है कि वे सतह पर थोड़े कठिन दिख सकते हैं, लेकिन जब आप वास्तव में उन पर काम करते हैं तो आप पाएंगे कि उनमें से अधिकतर दिखने की तुलना में कहीं अधिक आसान हैं। इसलिए आसान चीज़ों से खुश रहें और कठिन चीज़ों को लेकर अनावश्यक रूप से चिंतित न हों। 4. अपने प्रयास को प्राथमिकता दें हमेशा पहले आसान प्रश्नों का प्रयास करें और फिर प्रबंधनीय प्रश्नों की ओर बढ़ें और सुनिश्चित करें कि कठिन प्रश्नों को लेने से पहले आप उन्हें पूरा कर लें। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ रहे हैं जो आप जानते हैं। एक बार जब आप सभी आसान और प्रबंधनीय प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल कर लेंगे, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अधिक चुनौतीपूर्ण प्रश्नों को लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे। 5. गति और सटीकता सुनिश्चित करें यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं और आपके उत्तर सही हैं, गणना में तेज़ तरीकों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी पद ( +/- ) के चिह्न में त्रुटि करते हैं, तो आप द्विघात समीकरण या रैखिक समीकरण से जुड़े प्रश्नों को हल करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसलिए समय बचाने के लिए मूर्खतापूर्ण गलतियों से बचना बहुत महत्वपूर्ण है। गति रणनीतियों में हमने जिन तरकीबों पर चर्चा की है उनका हमेशा पालन करें। 6. अपनी घड़ी पर नजर रखें अपनी घड़ी पर नज़र रखने का

मतलब निश्चित रूप से आपका तनाव बढ़ाना नहीं है। यह केवल यह देखने के लिए है कि आप मोटे तौर पर उस समय आवंटन का पालन कर रहे हैं जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी। मामूली बदलाव बिल्कुल भी चिंता का कारण नहीं है। 7. किसी सवाल के बारे में ज्यादा सोचने से बचें प्रश्नों को हल करने से पहले उनके बारे में सोचना आवश्यक है; लेकिन इस हद तक नहीं कि आप एक प्रश्न पर बहुत सारा समय बर्बाद कर दें। इसके अलावा, आपको किसी प्रश्न का बहुत लंबा उत्तर सिर्फ इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रश्न आसान है और आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। याद रखें, आपको केवल प्रश्न का उत्तर देना है और कुछ नहीं। कोई भी अति-प्रयास केवल समय की बर्बादी होगी। 8. अपने उत्तरों को संशोधित करें आमतौर पर प्रश्न पत्र इस तरह से सेट किए जाते हैं कि सभी प्रश्नों को हल करने के बाद भी छात्रों के पास अंत में अपने उत्तर दोहराने के लिए 5-10 मिनट का समय बचे। अपना समय बर्बाद न करें और अपने सभी उत्तरों को दोबारा दोहराएं। 9. अपने विकल्पों का चयन सोच-समझकर करें कुछ प्रश्नों में आपको एकाधिक विकल्प प्रदान किये जायेंगे। जल्दबाजी न करें और समझदारी से अपना चुनाव करें। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें: उत्तर लिखना शुरू करने से पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। देखनाप्रश्न में क्या पूछा जा रहा है. 10. आसान भाषा का प्रयोग करें अपना उत्तर लिखते समय यह सुनिश्चित करें कि आप समझने में आसान भाषा का प्रयोग करें। एक परीक्षक बिना किसी वैचारिक भाषा के लेकिन फूलदार भाषा में लिखे गए वैचारिक उत्तर से अधिक प्रभावित होगा। 11. शब्द गणना का पालन करें प्रश्नों के लिए, विशेष रूप से भाषा और साहित्य के पेपरों में, जहां उत्तर के लिए शब्द गणना प्रदान की जाती है, शब्द गणना पर ही ध्यान दें। शब्द सीमा से अधिक न हो. इसके अलावा कंजूस न बनें और बहुत कम शब्दों में अपना उत्तर दें। 12. साफ सुथरा रहें अपना उत्तर साफ एवं सुपाठ्य लिखावट में लिखें। हर किसी की लिखावट सुंदर नहीं होती लेकिन कोई भी व्यक्ति उचित स्थान और विराम चिह्न के साथ सुपाठ्य लिखावट में उत्तर लिख सकता है। याद रखें कि यदि आपकी उत्तर पुस्तिका साफ-सुथरी नहीं है और लिखावट अस्पष्ट है तो यह आपके लिए प्रतिकूल होगा। जहां आवश्यक हो वहां मार्जिन का प्रयोग करें. 13. अपशब्दों के प्रयोग से बचें याद रखें कि लिखित अंग्रेजी, बोली जाने वाली अंग्रेजी से भिन्न होती है। कठबोली शब्दों या एसएमएस भाषा का उपयोग वर्तनी की गलती के रूप में गिना जाएगा और आपको इसके लिए दंडित किया जाएगा।

## भारत में 76वें गणतंत्र दिवस (2025) के अवसर पर शिक्षा की स्थिति

विजय गर्ग

भारत में 76वें गणतंत्र दिवस (2025) के अवसर पर शिक्षा की स्थिति में काफी प्रगति हुई है, लेकिन कई चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। यह स्थिति विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता, पहुंच, और प्रभाव को दर्शाती है।

शिक्षा की मौजूदा स्थिति (2025)

सुधार और प्रगति

1. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020):

शिक्षा को अधिक समावेशी और कौशल-आधारित बनाने के लिए प्रयास जारी हैं।

प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा के उपयोग और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया है।

5+3+3+4 ढांचा लागू किया जा रहा है, जिससे स्कूली शिक्षा को और मजबूत किया जा सके।

2. डिजिटल शिक्षा का विस्तार:

सरकार ने ₹ई-विद्या₹ और ₹दीक्षा पोर्टल₹ जैसे प्लेटफार्मों के जरिए डिजिटल शिक्षा को सशक्त बनाया है।

कोविड-19 के बाद से ऑनलाइन शिक्षा का महत्व बढ़ा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसका प्रभाव सीमित है।

3. उच्च शिक्षा और अनुसंधान:

उच्च शिक्षा में नई पहलें जैसे भारतीय विश्वविद्यालयों का अंतरराष्ट्रीयकरण और आईआईटी , आईआईएम, एनआईटी जैसे संस्थानों में अनुसंधान पर जोर दिया जा रहा है।

स्टार्टअप्स और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

चुनौतियाँ

1. ग्रामीण और शहरी विभाजन:

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का बुनियादी ढांचा कमजोर है।

डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट की कमी से छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा में दिक्कत होती है।

2. लैंगिक असमानता:

लड़कियों की शिक्षा में प्रगति के बावजूद, कई ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अभी भी वे स्कूल जाने से वंचित हैं।

3. गुणवत्ता में अंतर:

सरकारी और निजी स्कूलों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता का बड़ा अंतर बना हुआ है।

4. शिक्षा का बजट:

शिक्षा के लिए बजट का हिस्सा अपेक्षाकृत कम है।

सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और संसाधनों का अभाव है।

सरकार के प्रयास

1. सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास।

2. राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा मिशन का उद्देश्य डिजिटल साक्षरता बढ़ाना है।

3. कौशल विकास: युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौशल विकास केंद्र खोले जा रहे हैं।

आगे का रास्ता

76वें गणतंत्र दिवस पर, यह स्पष्ट है कि शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है।

सभी के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को मिलकर काम करना होगा ताकि भारत का हर बच्चा शिक्षित और सशक्त हो सके।

# भूजल स्तर में गिरावट और गुणवत्ता का सवाल

विजय गर्ग

भूजल के स्तर में तेजी से गिरावट व भूजल की गुणवत्ता जहां बड़े खतरे के संकेत हैं, वहीं साफ पेयजल की कमी के भीषण संकट की चेतावनी है। खासकर इसलिए कि धरती पर केवल तीन फीसदी ही मीठा पानी है जो हर जीव को जीवन दान देता है। दरअसल, धरती, समुद्र, उसके खारे पानी और धरती पर उपलब्ध मीठे पानी का निकट का रिश्ता है। जब हम धरती के आकार और उसकी जैव विविधता खासकर पेड़-पौधों से छेड़छाड़ करते है तो बारिश, जल प्रबंधन एवं जल उपलब्धता आदि पर व्यापक असर पड़ता है। भूजल भी इससे अछूता नहीं। भूजल का बढ़ता संकट यानी उसके भयावह स्तर तक गिरने का अहम कारण उसका बेतहाशा दोहन है जिसके चलते जमीन की भीतरी परत दिनोंदिन तेजी से सिकुड़ रही है। नतीजतन जमीन के धंसने का खतरा भी बढ़ रहा है। वहीं इससे भूमि की भीतरी परत ( एक्वीफायर ) की जलधारण क्षमता खत्म हो जाती है।

भारत में संभावित भूजल भंडार 432 लाख हैक्टर मीटर और दोहन योग्य सकल भूजल की मात्रा 396 लाख हैक्टर मीटर है। इस विशाल मात्रा का विकास, बरसाती पानी के, एक्वीफायर में रिसने के कारण होता है। यही पानी प्राकृतिक जल चक्र का अभिन्न अंग है। बारिश के दिनों में हर साल यह पुनर्जीवित होता है। अतः भूजल का दोहन, उसके अविरल प्रवाह तथा अवांछित घटकों के सुरक्षित निष्पादन को समझकर करना बेहद जरूरी है। वर्ष 1960 के बाद से पानी की मांग दोगुनी से अधिक हो गयी है। भूजल दोहन के मामले में हमारा देश शीर्ष पर है। देश का उत्तरी गांगेय इलाका तो भूजल दोहन के मामले में देश के दूसरे इलाकों के मुकाबले कीर्तिमान बना चुका है। राजधानी दिल्ली सहित समीप के कई शहरों का डार्क जोन में आना और दिल्ली एनसीआर में गंभीर पानी का संकट इसका सबूत है। नतीजतन, इस इलाके की जमीन की सतह का आकार तेजी से बदल रहा है। यहां धरती भी तेजी से धंसने लगी है। यह सिलसिला केवल एनसीआर तक ही नहीं बल्कि पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल और गुजरात तक जारी है। पंजाब के 23 जिलों में भूजल 'की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। दरअसल पंजाब की 94 फीसदी आबादी पीने के पानी के लिए भूजल पर ही निर्भर है। भूजल में बढ़ते प्रदूषण का यहां लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और वे गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

बीते दो दशकों में सिंचाई के लिए भूजल का अत्यधिक उपयोग हुआ है जिससे जहां भूजल की मांग बढ़ी वहीं गुणवत्ता खराब होती चली गयी। यहां भूजल में भारी धातुओं और रेडियो एक्टिव पदार्थों की मौजूदगी में तेजी से इजाफा हुआ। इसी प्रकार हरियाणा के 141 विकास खंडों में से 85 भूजल के अत्यधिक दोहन के चलते गंभीर स्थिति में हैं। यह हिस्सा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 60 फीसदी है। इससे राज्य की भूजल संकट की स्थिति का अंदाजा लग सकता है। गौरतलब यह है कि देश में भूजल निकासी का औसत 63 फीसदी है जबकि हरियाणा में भूजल निकासी 137 फीसदी से भी अधिक है। उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग ने दस महानगरों को अति दोहित की श्रेणी में रखा है और जल के दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नियमावली भी बनाई है। इसमें जुर्माना और कारावास दोनों का प्रावधान है। लेकिन यह नियमावली मात्र खानापूर्ति ही रह गयी है। वैज्ञानिक जलवायु में आ रहे बदलाव में भूजल दोहन की बड़ी भूमिका मानते है। ऐसे में भूजल प्रबंधन और भूजल उपयोग सम्बंधी रणनीतियों में व्यापक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। क्योंकि आबादी में बढ़ोतरी, बढ़ता शहरीकरण और कृषि भूमि पर गहन खेती के साथ ही लगातार भूजल की गिरावट हालात को और भयावह बना देगी।

कई अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि हिमालय की तलहटी से लेकर गंगा के मैदानों तक भूमि के व्यापक हिस्से में भूजल की बड़े पैमाने पर कमी हुयी है। वहीं आर्सेनिक, नाइट्रेट, सोडियम, यूरेनियम, फ्लोराइड आदि की अधिकता के कारण भूजल की खराब गुणवत्ता की चिंता केवल साफ पेयजल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सिंचाई के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रही है। आंध्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश के भूजल के 12.5 फीसदी नमूने उच्च सोडियम की मौजूदगी के कारण सिंचाई के लिए अनुकूल नहीं पाये गये हैं। देश के 440 जिलों के भूजल में बढ़ा नाइट्रेट स्तर गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा कर रहा है। सीजीडब्लयूबी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। पानी में नाइट्रेट प्रदूषण मुख्यतः नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों और पशु अपशिष्ट के अनुचित निपटान के कारण होता है। एक रिपोर्ट की मानें तो पानी के 9.04 फीसदी नमूनों में फ्लोराइड का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक और 3.55 फीसदी आर्सेनिक की मौजूदगी पायी गयी। यह प्रदूषण पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है। इससे कैंसर, किडनी, हड्डियों और त्वचा रोगों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है।

सिंचाई के भी उपयुक्त ना माने जाने वाले भूजल का प्रतिशत एक साल में 7.69 से बढ़कर 8.07 तक बढ़ गया है। पानी में लवणों की मौजूदगी लगातार बढ़ते जाना नाकामी ही है। जमीन पर सोडियम की परत जमना भी अच्छा संकेत नहीं है। जहां सोडियम की मात्रा सीमा से अधिक है, वहां विशेष अभियान चलाने के साथ प्रभावी निगरानी भी जरूरी है। देश में भूजल की गुणवत्ता में गिरावट के लिए उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल के उपचार की व्यवस्था न होना, खेती में अंधाधुंध उर्वरकों का इस्तेमाल, शहरीकरण, घरेलू कचरा मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। इन पर अंकुश लगाये बिना भूजल की गुणवत्ता हासिल कर पाना टेढ़ी खीर है।

# बाजरा बनाम परिष्कृत अनाज: अपने 2025 आहार के लिए बेहतर विकल्प बनाना

विजय गर्ग

शहरी जीवनशैली में बदलाव के कारण परिष्कृत अनाज, जैसे कि सफेद चावल और परिष्कृत गेहूं का आटा, जिसे 'मैदा' कहा जाता है, की खपत में भारी वृद्धि हुई है। इन अनाजों को मिलिंग और ब्लीचिंग का उपयोग करके अत्यधिक संसाधित किया जाता है ताकि बढ़िया आटा प्राप्त किया जा सके जिसका उपयोग रोजमर्रा की पाक तैयारियों में किया जाता है। ब्रेड, पास्ता, नूडल्स और केक जैसे उत्पाद मुख्य बन गए हैं, खासकर बच्चों के लिए जो अक्सर परिष्कृत आटे से बने खाद्य पदार्थ पसंद करते हैं। हालाँकि, शोध से पता चला है कि परिष्कृत अनाज के अधिक सेवन से वजन बढ़ता है, टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग और अन्य पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं। इसके विपरीत, बाजरा को न्यूनतम रूप से संसाधित किया जाता है और आम तौर पर इसका सेवन पूरे रूप में या आटे या फ्लेक्स के रूप में किया जाता है। बाजरा बीन, भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उगाई जाने वाली एक पेटेंट फसल है, जिसने अपने उच्च पोषण मूल्य के लिए लोकप्रियता हासिल की है। बाजरा एक बेहतर आहार विकल्प क्यों है: ● सतत कृषि: ● बाजरा कम उपजाऊ मिट्टी में न्यूनतम पानी की आवश्यकता के साथ उगाया जाता है, जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ फसल बन जाती है। ● उनकी खेती टिकाऊ कृषि पद्धतियों का समर्थन करती है, खासकर सूखा प्रभावित क्षेत्रों में। ● पोषण संबंधी पावरहाउस: ● फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और खनिज जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर, बाजरा आहार में अत्यधिक पौष्टिक है। ● वे ग्लूटेन-मुक्त हैं, जो उन्हें ग्लूटेन असहिष्णुता या सीलिएक रोग वाले लोगों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाते हैं। ● रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है: ● कोविड-19 के बाद, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भोजन विकल्पों की बढ़ती मांग को पूरा करते हुए, बाजरा ने अपनी प्रतिरक्षा-बढ़ाने वाले गुणों के लिए लोकप्रियता हासिल की है। ● किसान आजीविका का समर्थन करता है: ● अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 जैसी पहल ने बाजरा की खेती को प्रोत्साहित किया है, जिससे शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में किसानों की आजीविका में सुधार हुआ है। ● बहुमुखी और ट्रेंडी: ● बाजरा-आधारित उत्पाद भोजन, नाश्ते और यहां तक कि आधुनिक उपहार देने के विकल्प के रूप में भी एक लोकप्रिय विकल्प बन गए हैं, जो आधुनिक खाने के रुझान के अनुरूप हैं। ● पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ आहार विकल्प: ● बाजरा का चयन करके, उपभोक्ता अपने भोजन विकल्पों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में योगदान करते हैं। बाजरा बनाम परिष्कृत अनाज: अपने 2025 आहार के लिए बेहतर विकल्प बनाना 04:30 फैटी लीवर आहार: आपके लीवर के लिए सर्वोत्तम और सबसे खराब खाद्य पदार्थ बाजरा निर्यातकों के रूप में, हमने उनके कई स्वास्थ्य लाभों और स्थिरता के कारण वैश्विक स्तर पर भारतीय बाजरा की महत्वपूर्ण स्वीकार्यता देखी है। यूरोप, जीसीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के देश तेजी से बाजरा-आधारित उत्पादों का आयात कर रहे हैं क्योंकि उपभोक्ता अधिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए हैं और ग्लूटेन-मुक्त विकल्प तलाश रहे हैं। इस बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने पर ध्यान देने के साथ, भारत बाजरा का एक प्रमुख निर्यातक बन गया है। बाजरा की यह अंतरराष्ट्रीय मान्यता न केवल भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा दे रही है बल्कि वैश्विक स्तर पर पारंपरिक भारतीय सुपरफूड्स की दृश्यता भी बढ़ा रही है। यह उद्योग आनंददायक और पौष्टिक उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें भुना हुआ बाजरा और रागी के टुकड़े, बाजरा बिस्कुट, बाजरा वेफर्स, बाजरा चाय, मूसली,

मसाला छोला, बाजरा और अनाज बार, ज्वार इडली मिश्रण और आपके दोनों को संतुष्ट करने के लिए कई अन्य आकर्षक विकल्प शामिल हैं। स्वाद कलिकाएँ और पोषण संबंधी आवश्यकताएँ। जबकि परिष्कृत अनाज सुविधाजनक और व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, वे पोषण की दृष्टि से घटिया हैं और पर्यावरण की दृष्टि से कठिन हैं। इसके विपरीत, भारतीय सुपरफूड बाजरा एक पोषण पावरहाउस और एक टिकाऊ विकल्प है, जो उन्हें स्वास्थ्य और स्वास्थ्य दोनों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाता हैपर्यावरणीय लाभ। 2025 के लिए आहार विकल्पों में बाजरा को शामिल करके, व्यक्ति अपने समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार कर सकते हैं और टिकाऊ कृषि प्रथाओं का समर्थन कर सकते हैं। आगे देखते हुए, यह दशक ₹अनाज क्रांति₹ का वादा करता है। यह आंदोलन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को बाजरा की खेती का विस्तार करने के लिए सशक्त बनाएगा, अंततः एक स्वस्थ दुनिया में योगदान देगा और ₹स्वस्थ जीवन वापस लानेर का मार्ग प्रशस्त करेगा।

# अडानी ग्रुप के शेयरों में तूफानी तेजी, हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने का दिखा असर

परिवहन विशेष न्यूज

अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदाणी ग्रुप पर गंभीर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। अब यह कंपनी बंद हो गई है। इसका एलान खुद हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नेथन एंडरसन ने सोशल मीडिया पर किया। हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने के एलान का अदाणी ग्रुप के शेयरों पर काफी पॉजिटिव असर देखा जा रहा है। ग्रुप की कंपनियों के स्टॉक में 9 फीसदी तक उछाल आया है।

**नई दिल्ली।** अरबपति कारोबारी गौतम अदाणी के मालिकाना हक वाले अदाणी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में गुरुवार (16 जनवरी 2025) को जोरदार तेजी देखी जा रही है। इसकी वजह अमेरिकी शॉर्ट हिंडनबर्ग रिसर्च का बंद होना है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदाणी ग्रुप के खिलाफ गंभीर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। उस समय अदाणी ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयरों भारी गिरावट आई थी। आइए जानते हैं कि अदाणी ग्रुप के किस स्टॉक्स में कितनी तेजी आई है।

**Adani Group के किस स्टॉक में कितनी तेजी?**

शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान अदाणी ग्रुप की सभी कंपनियों में अच्छा उछाल दिखा। अदाणी पावर के शेयर की कीमत में 9.2 प्रतिशत (599.9 रुपये प्रति शेयर), अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयर की कीमत में 8.8 प्रतिशत (1,126.8 रुपये प्रति शेयर), अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर की कीमत में 7.7 प्रतिशत (2,569.85 रुपये प्रति शेयर), अदाणी टोटल गैस के शेयर की कीमत में 7.1 प्रतिशत (708.45 रुपये प्रति शेयर), अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर की कीमत में 6.6 प्रतिशत (832 रुपये प्रति शेयर) और अदाणी पोर्ट्स के शेयर की कीमत में 5.4 प्रतिशत (1,190 रुपये) की वृद्धि हुई। हालांकि, बाद में मुनाफावसूली के चलते इनमें कुछ करेक्शन भी हुआ।

**अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड**

इसके अलावा, अंबुजा सीमेंट्स के शेयर की कीमत में 4.5 प्रतिशत (542.9 रुपये प्रति शेयर), एसीसी के शेयर की कीमत में 4.1 प्रतिशत (2,054 रुपये प्रति शेयर) और एनडीटीवी के शेयर की कीमत में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 157.9 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गई।

**हिंडनबर्ग रिसर्च क्यों बंद हुई?**

हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नेथन एंडरसन ने 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करके हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'हमारा इरादा था कि हम जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं, उसके पूरा होने के बाद हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद कर दिया जाएगा। हमने हाल ही में कुछ कंपनियों की गड़बड़ियों को रेगुलेटर्स के साथ साझ किया है। इसी के साथ हमारा काम पूरा हो गया। अब हिंडनबर्ग रिसर्च को भंग किया जाता है।'

**हिंडनबर्ग ने अदाणी ग्रुप पर क्या आरोप लगाए थे?**

हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी 2023 में अदाणी ग्रुप पर तीखा हमला किया था। उसने एक रिपोर्ट जारी करके आरोप लगाया कि गौतम अदाणी का ग्रुप दशकों से लगभग 18 ट्रिलियन (218 बिलियन डॉलर) के स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी योजनाओं में शामिल था। अमेरिकी शॉर्ट-सेलर फर्म ने दावा किया था कि अदाणी परिवार ने भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी को बढ़ावा देने के लिए कैरिबियन, मॉरीशस और संयुक्त अरब अमीरात जैसे कर हेवन द्वीपों/देशों में ऑफशोर शेल संस्थाओं को नियंत्रित किया और समूह की सूचीबद्ध कंपनियों से पैसे निकाले।

**सेबी भी कर चुकी है अदाणी-हिंडनबर्ग मामले की जांच**

अदाणी ग्रुप ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था। इस मामले की सेबी ने भी अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में 24 में से 22 जांच पूरी कर ली थीं। बाजार नियामक ने हिंडनबर्ग और अदाणी ग्रुप की एक समूह कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। हालांकि, इस मामले पर अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने बाद में सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच पर भी अदाणी ग्रुप से मिलीभगत का आरोप लगाया था। सेबी चीफ ने हिंडनबर्ग रिसर्च के सभी आरोपों को खारिज कर दिया था।

# वॉलमार्ट ने जारी किया नया लोगो, सोशल मीडिया पर लोग बोले- क्या ये सच में नया है

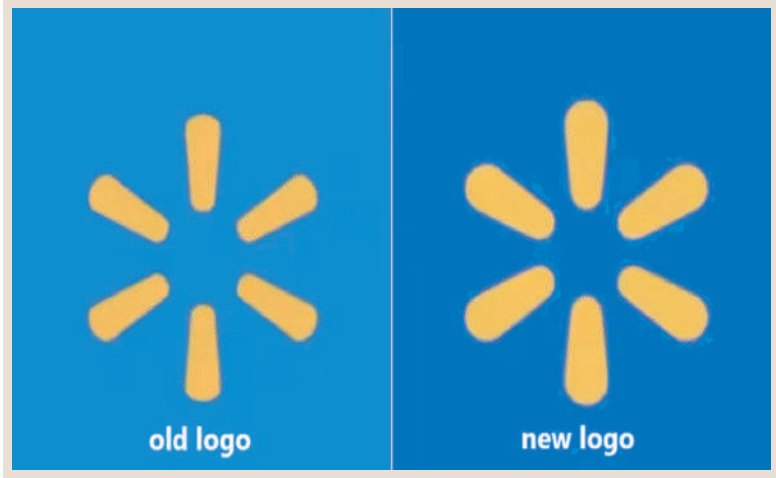


वॉलमार्ट ने 17 वर्षों में पहली बार अपने लोगो को अपडेट किया। जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कंपनी का नया लोगो अपडेट दरअसल पुराने जैसा ही दिख रहा है। कंपनी का कहना है कि यह एक रीब्रांडिंग रणनीति का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या किसी को इसके लिए भुगतान मिला? वहीं, बदलाव के बारे में बोलते हुए, वॉलमार्ट यूएस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य विपणन अधिकारी विलियम व्हाइट ने एक प्रेस बयान में कहा कि हमारे संस्थापक, सैम वाल्टन की विरासत में निहित यह अद्यतन, आज और कल के हमारे ग्राहकों की सेवा करने के लिए हमारी विकसित क्षमताओं और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

एक यूजर ने एक्स पर पूछा कि वालमार्ट का नया लोगो सच में नया है। तो दूसरे यूजर ने लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज, वॉलमार्ट ने अपने लोगो का शेड एक हेक्स कोड द्वारा बदलने के लिए लाखों खर्च किए। इनोवेशन अपने चरम पर...

वॉलमार्ट ने 17 वर्षों में पहली बार अपने लोगो को अपडेट किया। जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कंपनी का नया लोगो अपडेट दरअसल पुराने जैसा ही दिख रहा है। कंपनी का कहना है कि यह एक रीब्रांडिंग रणनीति का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या किसी को इसके लिए भुगतान मिला?

**नई दिल्ली।** वॉलमार्ट दुनियाभर की जानी मानी कंपनी है। कंपनी के लोगो से ही वॉलमार्ट को पहचान लेते हैं। वहीं, वॉलमार्ट ने 17 वर्षों में पहली बार अपने लोगो को अपडेट किया। जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कंपनी का नया लोगो अपडेट दरअसल पुराने जैसा ही दिख रहा है। कंपनी का कहना है कि यह एक रीब्रांडिंग रणनीति का हिस्सा है।

वहीं, सोशल मीडिया पर यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या किसी को इसके लिए भुगतान मिला? वहीं, बदलाव के बारे में बोलते हुए, वॉलमार्ट यूएस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य विपणन अधिकारी विलियम व्हाइट ने एक प्रेस बयान में कहा कि हमारे संस्थापक, सैम वाल्टन की विरासत में निहित यह अद्यतन, आज और कल के हमारे ग्राहकों की सेवा करने के लिए हमारी विकसित क्षमताओं और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

एक यूजर ने एक्स पर पूछा कि वालमार्ट का नया लोगो सच में नया है। तो दूसरे यूजर ने लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज, वॉलमार्ट ने अपने लोगो का शेड एक हेक्स कोड द्वारा बदलने के लिए लाखों खर्च किए। इनोवेशन अपने चरम पर...

# 8वें वेतन आयोग पर मुहर, केंद्रीय कर्मचारियों का कितना बढ़ेगा वेतन; समझिए पूरा कैलकुलेशन

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। इससे संभावित रूप से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। नरेंद्र मोदी के अगुआई वाली सरकार ने जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया था। इसकी सिफारिशें 31 दिसंबर 2025 को खत्म होंगी।

**नई दिल्ली।** केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। इससे संभावित रूप से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। नरेंद्र मोदी के अगुआई वाली सरकार ने जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया था। इसकी सिफारिशें 31 दिसंबर, 2025 को खत्म होंगी। इससे पहले, 4वें, 5वें और 6वें वेतन आयोगों का कार्यकाल 10 साल का था।

**8वें वेतन आयोग के बाद कितना बढ़ेगी सैलरी**

8th Pay Commission लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है। ऐसा होने पर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह 51,480 रुपये हो सकती है। अभी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। पेंशनभोगियों को भी इसी तरह फायदा मिलेगा। उनकी मिनिमम पेंशन अभी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।

**7वें वेतन आयोग लागू होने पर कितनी बढ़ी थी सैलरी**

7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में सबसे कम बढ़ोतरी हुई थी। इसमें सैलरी को फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के हिसाब से बढ़ाया गया, जिसे 2.57 गुना रखा गया था। इससे बेसिक सैलरी 18,000 रुपये हो गई। अगर इसी फॉर्मूले को आधार माना जाता है, तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की अधिकमत रेंज के तहत न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये हो जाएगी।

**फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?**

फिटमेंट फैक्टर दरअसल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल वाला फॉर्मूला है। इसके आधार पर अलग-अलग लेवल पर सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। हालांकि, इसमें भत्ते को नहीं जोड़ा जाता है।

**केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन कैसे-कैसे बढ़ा**

4th Pay Commission में केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 27.6 फीसदी थी। इसमें न्यूनतम वेतन 750 रुपये तय था।

5th Pay Commission में सैलरी में 31 फीसदी का बड़ा इजाफा किया गया। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन सीधे बढ़कर 2,550 रुपये महीना हो गया था।

6th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर को लागू हुआ। तब इसे 1.86 गुना रखा गया था। इससे कर्मचारियों को सैलरी में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिलाष उनकी न्यूनतम सैलरी में 54 फीसदी बढ़ी और बेसिक सैलरी बढ़कर 7000 रुपये हो गई.

साल 2014 में 7th Pay Commission का गठन हुआ। फिटमेंट फैक्टर को आधार मानते हुए 2.57 गुना की वृद्धि की गई। लेकिन, वेतन वृद्धि सिर्फ 14.29 फीसदी ही हुई।

# असली मालिक का पता न चलने पर भी कुर्क की जा सकती है बेनामी संपत्ति, कोर्ट का अहम फैसला

परिवहन विशेष न्यूज

आयकर विभाग की लखनऊ इकाई ने 2023 में लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में 3.47 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की कई संपत्तियां कुर्क की। इन संपत्तियों को रियल एस्टेट समूहों द्वारा बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी का उपयोग करके खरीदा गया था जो बेनामी लेनदेन का एक सामान्य संकेत है जहां संपत्ति किसी और के नाम पर होती है लेकिन असली मालिक अलग होता है।

**नई दिल्ली।** आयकर विभाग बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध (पीबीपीटी) अधिनियम 1988 के तहत उस स्थिति में भी किसी संपत्ति को कुर्क कर सकता है, जबकि उस संपत्ति के वास्तविक मालिक की पहचान नहीं हुई हो। कानून में इस स्थिति से निपटने के लिए विशिष्ट प्रविधान हैं। बेनामी रोधी कानून से संबंधित न्यायाधिकरण ने यह बात कही।

**आयकर विभाग की छापेमारी के बाद हुआ खुलासा**

पिछले साल 26 नवंबर को आयकर विभाग की लखनऊ इकाई द्वारा जारी भूमि संपत्ति कुर्की आदेश को न्यायाधिकरण ने बरकरार रखा। यह मामला तब सामने आया जब विभाग ने लखनऊ स्थित तीन रियल्टी समूहों के परिसरों पर छापे मारे। इन समूहों ने काकोरी क्षेत्र में बड़े भूखंड बेहिसाब नकदी से खरीदे थे।

**किसी भी लाभार्थी स्वामी का नाम नहीं**

लखनऊ स्थित बेनामी निषेध इकाई (बीपीयू) ने अक्टूबर 2023 में काकोरी में 3.47 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की पांच भूमि कुर्क करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश में एक बेनामीदार के अलावा दो कंपनियों और दो व्यक्तियों को हितधारक के रूप में नामित किया गया था। हालांकि, किसी भी लाभार्थी स्वामी का नाम नहीं था।

**आयकर विभाग द्वारा बेनामी संपत्ति की कुर्की**

आमतौर पर जब आयकर विभाग द्वारा बेनामी संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी किया जाता है तो उसमें बेनामीदार और लाभार्थी स्वामी का नाम होता है, लेकिन इस मामले में न्यायाधिकरण ने आयकर कुर्की आदेश की आंशिक पुष्टि की है, जिसमें 3.47 करोड़ रुपये में से 3.10 करोड़ रुपये की संपत्ति शामिल है। इस मामले में एक्सेला नामक रियल एस्टेट कंपनी के ऑफिस ब्वाय रवि कुमार को बेनामीदार के रूप में पहचाना गया है।

**बेनामी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई**

आयकर विभाग बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध (पीबीपीटी) का यह फैसला दर्शाता है कि कानून के तहत बेनामी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आयकर विभाग के पास पर्याप्त अधिकार हैं, भले ही वास्तविक मालिक की पहचान न हो।

# क्यों बंद हुई हिंडनबर्ग रिसर्च, कौन हैं नेथन एंडरसन; जानें पूरी डिटेल

परिवहन विशेष न्यूज

अमेरिका की चर्चित शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च बंद हो गई। इसका एलान खुद हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नेथन एंडरसन ने किया। इसने अदाणी ग्रुप समेत कई बड़ी कंपनियों पर गंभीर वित्तीय धांधली के आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग ने अगस्त 2024 में अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि SEBI चीफ माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अदाणी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है।

**नई दिल्ली।** अमेरिकी शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च पर ताला लगने जा रहा है। यह कंपनी भारत में अदाणी ग्रुप के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाकर चर्चा में आई थी। फाउंडर नेथन एंडरसन ने बुधवार देर रात हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने का एलान किया। हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत 2017 में हुई थी। यह बड़ी कंपनियों की वित्तीय धांधली का पर्दाफाश करने का दावा करती थी।

**हिंडनबर्ग रिसर्च क्यों बंद हो रही है?**

नेथन एंडरसन का कहना है कि हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का फैसला काफी सोच-समझकर लिया गया है। हालांकि, उन्होंने कंपनी को बंद करने का कोई सटीक कारण नहीं बताया। एंडरसन का कहना है कि कंपनी की शुरुआत जिस मकसद को लेकर की गई थी, उसे पूरा होने के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म को बंद करने के फैसले के बारे में स्पष्ट किया कि यह बेहद निजी फैसला है। उन्होंने कहा, 'कोई एक खास बात नहीं है- कोई विशेष खतरा नहीं, कोई हेल्थ इश्यू नहीं और कोई बड़ा व्यक्तिगत मुद्दा नहीं।'

**हिंडनबर्ग ने किन कंपनियों को निशाना बनाया था?**

हिंडनबर्ग रिसर्च ने कई बड़ी कंपनियों के खिलाफ गंभीर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। इनमें भारत का अदाणी ग्रुप और अमेरिका का इकान एंटरप्राइजेज शामिल है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने इन कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। अदाणी ग्रुप को सबसे अधिक झटका लगा था। जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी, तो अदाणी ग्रुप के मालिक गौतम अदाणी दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स थे।

लेकिन, रिपोर्ट आने के बाद ग्रुप की सभी लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई। अदाणी उस समय टॉप 20 रईसों की लिस्ट से भी बाहर बाहर हो गए थे। पिछले साल अगस्त में SEBI चीफ माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अदाणी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी होने का दावा भी किया था।

**कौन हैं नेथन एंडरसन (Nathan Anderson)?**

हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर और प्रमुख विश्लेषक नेथन एंडरसन थे। एंडरसन और उनकी फर्म को सार्वजनिक तौर पर अलग-अलग कंपनियों के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें कथित रूप से वित्तीय धोखाधड़ी के मामले उजागर करने का दावा किया गया है। उनकी रिपोर्ट को मीडिया और कारोबार जगत में काफी गंभीरता से लिया जाता था। इससे खासकर लिस्टेड कंपनियों के शेयरों पर काफी बुरा असर पड़ता था।

एंडरसन अपने काम की वजह से अक्सर विवादों में रहें, उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। हालांकि, एंडरसन ने हमेशा दावा किया कि उन्होंने जो कुछ भी किया, उसका मकसद कारोबार जगत की गंदगी को निवेशकों के सामने लाना था।

**हिंडनबर्ग नाम रखने की वजह क्या थी?**

6 मई 1937 को एक गंभीर हवाई हादसा हुआ। ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में हिंडनबर्ग नाम का एक जर्मन एयर स्पेसशिप उड़ान भरते समय हवा में ही क्रैश हो गया। इस हादसे में 35 लोगों की मौत हुई थी। जांच में पता चला कि कंपनी ने नियमों को ताक पर रखर क्षमता से ज्यादा लोगों को विमान में बिठा दिया था, जिसके चलते हादसा हुआ। एंडरसन का मानना था कि कंपनी अगर नियमों का पालन करती, तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता।

इसीलिए एंडरसन ने 2017 में अपनी कंपनी का नाम 'हिंडनबर्ग' रखा था। एंडरसन का दावा था कि वह वित्तीय गड़बड़ी करने वाली कंपनियों की पोल खोलना चाहते हैं, ताकि हिंडनबर्ग एयरशिप जैसा हादसा शेयर बाजार की दुनिया में न हो। और निवेशकों को अपने खून-पसीने की कमाई न गंवानी पड़े।

# किस उम्र में खरीदें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, किन बातों का रखें ध्यान?

परिवहन विशेष न्यूज

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बीमारियों की चपेट में आने का खतरा अधिक रहता है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी हो जाता है। इससे बीमारियों के इलाज का बोझ कम हो जाता है। आइए जानते हैं कि आपको किस उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए और इसे लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

**नई दिल्ली।** आज की लाइफस्टाइल में बीमारियों और शरीर का अटूट रिश्ता बन गया है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस लेना काफी जरूरी हो जाता है। इससे आपके लिए बेहतर इलाज के रास्ते खुलते हैं और उनका आपकी वित्तीय स्थिति पर कोई बोझ भी नहीं पड़ता। हेल्थ इंश्योरेंस में उम्र एक बड़ा फैक्टर रहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आपको किस उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए और इसे लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

**किस उम्र में लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस?**

आप हेल्थ इंश्योरेंस को जितना जल्दी लेंगे, उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि यह आपके लिए फौरन एक वित्तीय सुरक्षा कवच बन जाता है। अगर पैरेंट्स के पास जॉब है, तो अमूमन उन्हें कंपनी की ओर से इंश्योरेंस मिलता है। इसमें कई बार बच्चों का कवरेज भी शामिल होता है। अगर आपके पास पैरेंट्स के इंश्योरेंस का कवर नहीं है, तो आपको तुरंत हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। 25 साल की उम्र के बाद तो आपके पास हर हाल में हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। क्योंकि उम्र के इस पड़ाव के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ने लगता है।

**कम उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के फायदे**

अगर आप कम उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे, तो आपको कम प्रीमियम देना होगा। बीमा कंपनियां प्रीमियम उम्र और मेडिकल कंडीशन देखकर तय करती हैं। कम उम्र के साथ मेडिकल हिस्ट्री क्लीन होने पर इंश्योरेंस का प्रीमियम काफी कम हो जाता है। वहीं, उम्र बढ़ने के साथ सेहत से जुड़ी दिक्कतें होने लगती हैं, जिससे प्रीमियम बढ़ जाता है।

कम उम्र में पॉलिसी खरीदने पर अच्छा कवरेज मिलने की उम्मीद रहती है। कंपनियों को कम उम्र वाले ग्राहकों के लिए क्लेम की टेंशन काफी कम होती है। इसलिए वे युवा ग्राहकों को लुभाने के लिए कई बार शानदार कवरेज ऑफर करती हैं।

**हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त किन बातों का रखें ध्यान**

हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए इनके बारे में जानते हैं:

- हेल्थ इंश्योरेंस के कवर की रकम अपनी जरूरत और बजट के मुताबिक चुनें।
- बीमा के प्रीमियम की दर की तुलना करें और अपने बजट के अनुसार चुनें।
- क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखें, जिससे कंपनी की क्लेम सेटलमेंट का पता चलता है।
- नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट जरूर चेक करें, जो आपके क्षेत्र में उपलब्ध हैं।
- अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, तो प्री-एक्सिस्टिंग डिजीज कवरेज की जांच करें।

# दिल्ली में 'पिंक पास' स्कीम का महिलाओं की ज़िंदगी पर क्या असर रहा?- ग्राउंड रिपोर्ट

चुनावों में महिला वोटर को लेकर अब सियासी दल गंभीर नज़र आने लगे हैं और उनके वोट हासिल करने के लिए अलग-अलग रणनीति बनाने लगे हैं. हाल में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 'लाडली बहना योजना' का नतीजों पर असर देखने को मिला.

दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ़्त बस सेवा की एक योजना चल रही है. इसे 'पिंक पास' प्रोग्राम कहा जाता है. सवाल है, क्या आगामी विधानसभा चुनाव में वोट देते वक़्त महिला मतदाताओं के लिए यह मुद्दा होगा?

दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार है. ज़ाहिर है, चुनाव के वक़्त उनके वादों और उन वादों की ज़मीनी हक़ीक़त की पड़ताल भी होगी.

हमने महिलाओं की ज़िंदगी में 'पिंक पास' का असर देखने की कोशिश की.

कोहरे की परत से ढकी 10 जनवरी की एक सर्द सुबह. नंद नगरी की संकरी गलियों से 24 साल की भावना बस स्टॉप की ओर बढ़ रही हैं. इस इलाक़े में राजधानी का बड़ा कामकाजी वर्ग रहता है.

स्टॉप पर महिलाओं की एक टोली बस का इंतज़ार कर रही है. भावना भी इनमें शामिल हो जाती हैं. उसे बस नंबर- 234 पकड़कर सीलमपुर जाना है.

भावना के माता-पिता की मौत हो चुकी है. इसके बाद उन्होंने घर से बाहर निकलकर काम करने का फ़ैसला किया. अब वह कढ़ाई का काम करती हैं. वे इतने दिनों में दिल्ली की बसों में यात्रा करने में माहिर हो गई हैं.

भावना बताती हैं, ₹पहले मैं घर से बाहर निकली ही नहीं थी. मजबूरी में मैंने काम करना शुरू किया. मुझे लगता था कि अगर बाहर जाकर काम करने लगी तो शायद पैसे नहीं बचा पाऊँगी. यहाँ रहने वाले लोगों की औसतन 10 हज़ार रुपये महीने की कमाई होती है. अगर हम बस या आने-जाने पर ख़र्च करने लगे तो कोई बचत नहीं होगी.₹

उनका कहना है, ₹इस मुफ़्त बस यात्रा के कारण ही मेरे लिए आत्मनिर्भर होना मुमकिन हो पाया.₹

हाल ही में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी है. अब वह नई नौकरी की तलाश में और इंटरव्यू देने के लिए शहर में जगह-जगह जा रही हैं. मुफ़्त बस सेवा की वजह से कहीं भी आने-जाने के बारे में उन्हें सोचना नहीं पड़ रहा है.

भावना की बातों और दिल्ली सरकार की योजना से यह तो समझ आ रहा है कि दिल्ली का क्षेत्रफल भले ही 1,483 वर्ग किलोमीटर हो, लेकिन महिलाओं के लिए रोज़गार पर जाने की कोई सीमा नहीं रही.

वो दिल्ली के किसी भी इलाक़े में काम के लिए आ-जा सकती हैं.

दिल्ली चुनाव के प्रचार के दौरान 'आप' और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) दोनों महिलाओं के लिए विशेष योजनाएँ लागू करने का वादा कर रही हैं.

मुफ़्त बिजली और पानी के अलावा महिलाओं तक कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार और उनके वितरण का मुद्दा राजनीतिक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण हो गया है.

आम आदमी पार्टी ने दिसंबर में राजधानी में 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' की राशि बढ़ाने की घोषणा भी की है.

आप ने यह घोषणा की थी कि अगर वह दिल्ली विधानसभा चुनाव फिर जीतती है तो इस योजना के तहत मिलने वाले भत्ते को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये कर देगी.

23 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण भी शुरू कर दिया था.

**मुफ़्त बस यात्रा योजना**

**डीटीसी बस सेवा**

'आप' की ध्यान आकर्षित करने वाली योजनाओं में महिलाओं के लिए मुफ़्त बस यात्रा योजना भी शामिल है. इसे पाँच साल पहले 2019 में शुरू किया गया था.

इस योजना के तहत महिलाएँ दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (डीआईएमटीएस) द्वारा संचालित सभी एसी और नॉन-एसी बसों में मुफ़्त यात्रा कर सकती हैं. दिल्ली सरकार का दावा है कि अब तक 150 करोड़ से ज्यादा 'पिंक टिकट' बिक चुके हैं.

जैस्मिन शाह 'आप' के सदस्य और 'दिल्ली मॉडल' किताब के लेखक हैं. उन्होंने मुफ़्त बस की नीति बनाने में मदद की है.

वो अपने एक लेख में लिखते हैं, ₹आशोका विश्वविद्यालय और शिव नादर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक स्वतंत्र अध्ययन किया था. यह अध्ययन दिखाता है कि इस योजना के कारण समाज के हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के लिए रोज़गार में 24 परसेंटेज प्वाइंट का इज़ाफ़ा हुआ है. इस योजना का लाभ उन महिलाओं को हुआ है, जो किफ़ायती सार्वजनिक परिवहन से सबसे अधिक लाभ उठा सकती हैं.₹

**प्रोफ़ेसर डॉ. रीतिका खेड़ा**

प्रोफ़ेसर डॉ. रितिका खेड़ा एक मशहूर विकास अर्थशास्त्री हैं. उनका कहना है कि वह इन नीतियों को लोक-लुभावन नहीं मानतीं. वो इसे एक सही दिशा में उठाया गया कदम मानती हैं. यह लोगों के अधिकार से जुड़ा है.

रितिका कहती हैं, ₹महिलाओं के लिए सार्वजनिक बसों में सब्सिडी या रियायती टिकटों का एक बहुत लंबा इतिहास है. अन्य राज्यों ने भी यह कदम उठाया है. इसका आर्थिक महत्व भी है."

"कार्यबल में महिलाओं की संख्या बहुत कम है. अगर वे अपनी ख़ुद की कमाई नहीं कर रही हैं तो वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं. इसीलिए भले ही उनकी अपनी आय न हो, मुफ़्त बस यात्रा उन्हें कम से कम आने-जाने की कुछ आज़ादी तो देती है."

"इसके अलावा, जो लोग बसों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ज्यादातर स्कूल या कॉलेज जाने वाली युवा महिलाएँ होती हैं. इस लिहाज़ से यह उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण का भी एक तरह से सब्सिडीकरण है. शायद इससे महिलाओं की अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी.₹

ऐसी ही एक महिला हैं 28 साल की सुनीता. वे दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाक़े की रहने वाली हैं. सुनीता एक समाजसेवी और लेखिका भी हैं.

## दिल्ली में बसों का किराया

| दूरी | सामान्य बस | एसी बस |
|---|---|---|
| 4 किलोमीटर तक | 5 रुपये | 10 रुपये |
| 4 से 10 किलोमीटर | 10 रुपये | 15 रुपये |
| 10 से 12 किलोमीटर | 15 रुपये | 20 रुपये |
| 12 किलोमीटर से ज्यादा | 25 रुपये | 25 रुपये |

वह कहती हैं, ₹जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था तब बसें मुफ़्त नहीं थीं. मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में दाख़िला मिला था. यह शहर के दूसरे हिस्से में था. मेरे परिवार को मुझे वहाँ भेजने की इच्छा नहीं थी. वे मेरी सुरक्षा के बारे में चिंतित थे. साथ ही यह भी सोचते थे कि मुझे वहाँ भेजना बहुत महँगा पड़ेगा."

₹आने-जाने की आज़ादी ने मुझे सशक्त बनाया' मुझे बाहर जाने का आत्मविश्वास मिला. मैं बैंक भी जाती थी. घर के काम करती थी. उसके साथ-साथ, मैं शहर भी घूम पाई. मुझे बाहर जाने की स्वतंत्रता भी मिली.₹

हालाँकि सुनीता कहती हैं कि मुश्किलें अभी भी बहुत सी हैं.

'महिला सम्मान स्कीम' पर सरकारी नोटिस से कैसे आम आदमी पार्टी पर उठ रहे सवाल

25 दिसंबर 2024

आम आदमी पार्टी की 'महिला सम्मान योजना' की होगी जांच, एलजी के आदेश पर क्या बोले केजरीवाल?

28 दिसंबर 2024

बीजेपी के सामने दिल्ली में क्या है चुनौती, क्यों नहीं बना पाती है सरकार?

6 जनवरी 2025

महिलाएँ हैं, मुफ़्त सवारी नहीं

सुनीता बस स्टैंड पे

इमेज कैप्शन,एक अस्थाई बस स्टैंड पर खड़ी सुनीता का कहना है कि ड्राइवरों को और संवेदनशील होने की ज़रूरत है.

सुनीता एक पेड़ के पास खड़ी हैं. इसके पास सुंदर नगरी बस स्टॉप का लेबल लगा है. लेकिन यहाँ स्टॉप का किसी तरह का ढाँचा मौजूद नहीं है.

सुनीता ध्यान दिलाती हैं, ₹इस योजना ने बसों को सुलभ ज़रूर बना दिया है, लेकिन बसों को चलाने वाले लोग अभी भी संवेदनशील नहीं हैं. वे महिलाओं को मुफ़्त सवारी करने वालों के रूप में देखते हैं. वे जब समूह में महिलाएँ देखते हैं तो अक्सर बसें रोकते नहीं हैं."

हालाँकि, वो कहती हैं, "लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा अब भी सुरक्षा है.₹

सुनीता याद करती हैं कि कैसे एक बार बस में एक मर्द ने उनके साथ शारीरिक बदतमीज़ी की थी.

वह कहती हैं, ₹मैं कभी नहीं भूलूँगी. यह हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा. बसें सशक्त कर सकती हैं, लेकिन सुरक्षा अभी भी एक चिंता का विषय है.₹

**सुधार की और ज़रूरत**

विद्या

इमेज कैप्शन,विद्या (पिंक स्वेटर में) का कहना है कि अक्सर ड्राइवर महिलाओं को देख बस नहीं रोकते हैं.

मुफ़्त बस यात्रा योजना ने लड़कियों और महिलाओं की गतिशीलता बढ़ाई है. उनके खर्चों को बचाने में मदद की है. हालाँकि, दूसरी तरफ एक बड़ी संख्या में महिलाएँ बसों में असुरक्षित भी महसूस करती हैं.

उनमें से कुछ का कहना है कि उन्हें मुफ़्त यात्रा करने के लिए पुरुष अक्सर अपमानित करते हैं. कई बार उन्हें बसों में चढ़ने नहीं दिया जाता.

स्वयंसेवी संगठन ग्रीनपीस इंडिया ने साल 2024 में 'राइडिंग द जस्टिस रूट' नाम की एक रिपोर्ट जारी की थी. इसमें 500 महिलाओं का सर्वेक्षण किया गया था.

इस रिपोर्ट के मुताबिक, शहर की 80 फ़ीसदी से ज्यादा महिलाओं ने कहा कि उनके लिए बसें निर्धारित स्थान पर नहीं रुकतीं.

विद्या एक फैक्ट्री में काम करती हैं. वे गगन थिएटर बस स्टैंड से मौजपुर जाने के लिए बस पकड़ती हैं.

बस का इंतजार करते हुए वह कहती हैं, ₹मैं आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ, जब बस ड्राइवर महिलाओं को देखते हैं तो वह बस नहीं रोकते हैं. मेरा यह हमेशा का संघर्ष रहता है कि मैं समय पर कैसे पहुँच सकूँ.₹

यही नहीं, ग्रीनपीस की रिपोर्ट के अनुसार 75 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ दिल्ली की बसों में रात के समय यात्रा करते हुए असुरक्षित महसूस करती हैं.

दीपाली टोंक ग्रीनपीस इंडिया के साथ काम करती हैं. वह कहती हैं, ₹इस योजना ने निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव किए हैं. महिलाओं की मोबिलिटी और सार्वजनिक स्थलों तक उनकी पहुँच के संदर्भ में एक स्थायी प्रभाव डाला है."

दीपाली बताती हैं, "हालाँकि, हमने यह सुझाव दिया है कि दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन में महिला स्टाफ़ की संख्या बढ़ाई जाए. उचित बस स्टॉप बनाए जाएँ. बसों में मार्शल हों. ये सब महिलाओं के लिए दिल्ली में यात्रा के अनुभव को पूरी तरह से बदल सकती हैं.₹

दूसरे राज्यों ने भी दिल्ली सरकार की तरह महिलाओं के लिए मुफ़्त बस यात्रा की योजनाएँ शुरू की हैं.

तमिलनाडु, पंजाब और केरल में यह योजना साल 2021 में शुरू हुई. वहीं कर्नाटक में इसे साल 2023 में शुरू किया गया.

मीडिया और राजनीति के बीच मनमोहन सिंह की चुप्पी के पीछे की क्या थी रणनीति?

29 दिसंबर 2024

आतिशीः ख़ाली कुर्सी बग़ल में लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लोकतांत्रिक देश में क्या मायने हैं?

29 सितंबर 2024

हरियाणा में कांग्रेस क्यों हारी, इन चार कारणों से समझिए

8 अक्टूबर 2024

ट्रांस महिलाओं के साथ भेदभाव

इमेज कैप्शन,दिल्ली सरकार ने फरवरी 2024 में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी मुफ़्त बस यात्रा योजना शुरू करने की घोषणा की थी.

तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फरवरी 2024 में घोषणा की थी कि दिल्ली सरकार जल्द ही ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी मुफ़्त बस यात्रा योजना शुरू करेगी. इसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को राज्य संचालित बसों में यात्रा करते समय किराया नहीं देना होगा.

हालाँकि, इस घोषणा का स्वागत करते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय ने ज़मीनी वास्तविकता की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की है.

ट्वीट (टीडब्ल्यूईईटी) फाउंडेशन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सशक्त बनाने और उन्हें कौशल सिखाने का काम करता है. यह संस्था ट्रांस महिलाओं को ट्रेनिंग देती है. उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करती है.

बीबीसी हिंदी ने इस संगठन में कोर्स करने वाली युवा ट्रांस महिलाओं उर्वी और दीपिका से बात की.

उर्वी ने बताया, ₹मैं नोएडा से आती हूँ. हरकेश नगर में फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करती हूँ. मैं बस से आती-जाती हूँ. ट्रांस महिलाओं के लिए अभी भी बसों में सफ़र बहुत मुश्किल है.₹

वो कहती हैं कि ट्रांस व्यक्तियों को अपनी पहचान की वजह से भी कई बार दिक़्क़त होती है. उनके कहने से कोई उन्हें ट्रांस नहीं मानता, बल्कि उन्हें अपने हाव-भाव से ज़ाहिर करने पर मजबूर होना पड़ता है.

इनसे बातचीत में एक बड़ा मुद्दा शारीरिक बदतमीज़ी और भेदभाव का सामने आया. ट्रांस महिलाओं को अक्सर इनका सामना करना पड़ता है.

सौम्या गुप्ता ट्वीट फ़ाउंडेशन की संस्थापक सदस्य हैं. वे इस मुद्दे पर आगे का रास्ता सुझाती हैं. उनका कहना है, ₹हम इस योजना का स्वागत करते हैं. हालाँकि, हमारे कुछ सुझाव भी हैं—जैसे, सीटों का आरक्षण. ट्रांस लोगों के लिए सीटें आरक्षित की जानी चाहिए ताकि वे यात्रा करते समय सुरक्षित महसूस कर सकें."

"इसके अलावा, बस स्टॉप पर शौचालयों की सख़्त ज़रूरत है. शौचालयों के बिना सड़क पर यात्रा करना बेहद मुश्किल है. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने की सख़्त आवश्यकता है.₹

इस तरह, जहाँ दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ़्त बस यात्रा योजना का ऐलान किया है, वहीं समुदाय के सशक्तीकरण और सुरक्षा से जुड़े कई गंभीर मुद्दे और सुझाव सामने आए हैं.

यह इस योजना के असरदार तरीक़े से लागू होने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं.

> "कार्यबल में महिलाओं की संख्या बहुत कम है. अगर वे अपनी ख़ुद की कमाई नहीं कर रही हैं तो वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं. इसीलिए भले ही उनकी अपनी आय न हो, मुफ़्त बस यात्रा उन्हें कम से कम आने-जाने की कुछ आज़ादी तो देती है."
>
> प्रोफ़ेसर डॉ. रीतिका खेड़ा
> प्रसिद्ध विकास अर्थशास्त्री

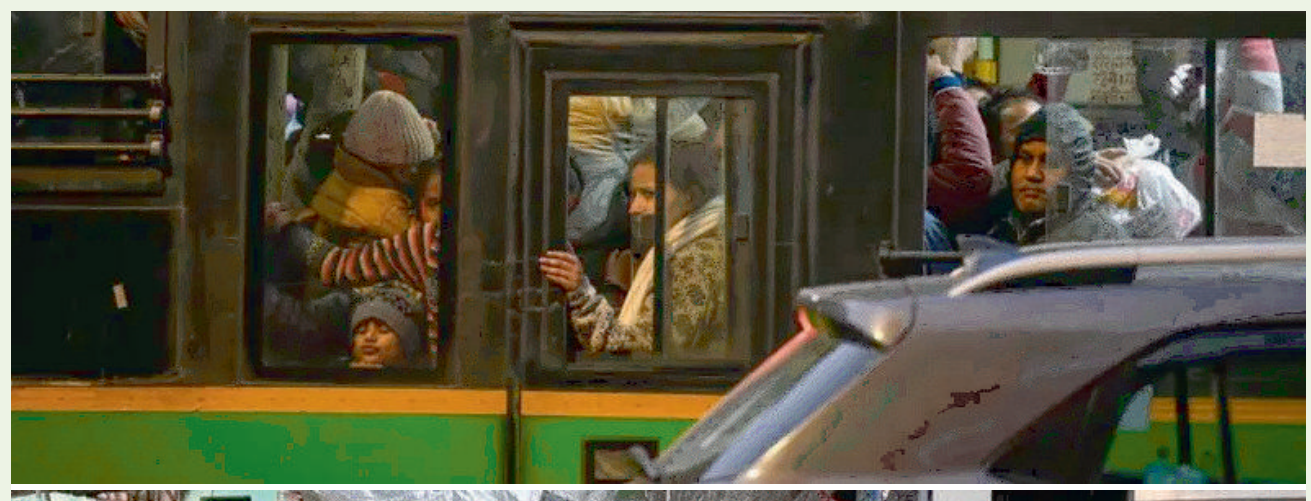

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। **RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023**